दैनिक

सांध्य प्रकाश

भोपाल की धड़कन

वर्ष 54/ अंक 320/ पृष्ठ 8 / मूल्य ₹ 2.10

संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल

■आर.एन.आई 22296/71 ■डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14

भोपाल, शनिवार 05 जुलाई 2025 भोपाल से प्रकाशित

dainiksandhyaprakash.in

सांध्यप्रकाश विशेष

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष ने कहा, डेडलाइन नहीं, देशहित पहले

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत किसी समय सीमा के दबाव में व्यापार समझौते नहीं करेगा। गोयल ने जोर देकर कहा कि कोई भी समझौता देश के हित और आपसी लाभ को ध्यान में रखकर ही होगा। गोयल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम डेडलाइन के आधार पर समझौते नहीं करते। भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। हमारा पहला लक्ष्य देश और जनता के हितों की रक्षा करना है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दोनों देश जुलाई 2025 तक एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए गहन बातचीत में जुटे हैं। बता दें, भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम पर 26त्न टैरिफ लगाने के जवाब में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जवाबी टैरिफ की चेतावनी दी है। हालांकि, अमेरिका ने भारत पर यह टैरिफ 9 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।गोयल ने कहा, हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों को महत्व देते हैं और सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और पेरू जैसे अन्य देशों के साथ भी व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, लेकिन हर समझौता भारत की शर्तों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर होगा। यह वार्ता उस समय हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत समेत कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी। गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा और व्यापार सौदा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होना चाहिए।

वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश ने रचा इतिहास नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को दी मात

जागरेब। भारतीय शतरंज के उभरते सितारे और विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने ग्रैंड शतरंज टूर रैपिड 2025 के जागरेब चरण में छठे राउंड में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को काले मोहरों से हराकर सनसनी मचा दी। इस जीत के साथ गुकेश 10 अंकों के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। पहले दिन तीन में से दो मुकाबले जीतने वाले गुकेश ने चौथे और पांचवें राउंड में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और अमेरिका के फैबियानो कारूआना को हराया था। यह उनकी कार्लसन पर लगातार दूसरी जीत है, इससे पहले उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 में भी कार्लसन को मात दी थी। टूर्नामेंट में गुकेश की यह लगातार पांचवीं जीत है, जिससे वह पोलैंड के डुडा जान क्रिस्टोफ पर दो अंक की बढ़त बनाए हुए हैं। मैच से पहले कार्लसन ने गुकेश को कमजोर खिलाड़ी कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन गुकेश ने अपनी चालों से जवाब दिया। पूर्व विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कार्लसन पर तंज कसा, यह कार्लसन की सिर्फ हार नहीं, बल्कि उनके वर्चस्व पर सवाल है। रैपिड वर्ग में तीन दौर बाकी हैं, और अब ब्लिट्ज फॉर्मेट के दो मुकाबले होने हैं। क्या गुकेश अपना दबदबा कायम रखेंगे या कार्लसन वापसी करेंगे, यह देखना रोमांचक होगा।

सीएम डॉ मोहन और बीजेपी अध्यक्ष खंडेलवाल ने की पूर्व मंत्री गौरीशंकर से मुलाकात

भोपाल। सीएम डॉ मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमन्त खंडेलवाल ने की पूर्व मंत्री गौरीशंकर से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हेमंत खंडेलवाल पूर्व मंत्री से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा- आज हम लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर मिलने आए हैं। ऐसे ही कुशलक्षेम पूछने आए हैं। आगामी विधानसभा सत्र भी आने वाला है। ऐसे में हमारे विधायकों को आपके लंबे संसदीय जीवन का लाभ मिले, सहज रूप में मिलने आए हैं।

कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष दिन है। जिसके अवसर पर प्रदेश के अंदर दो तरह के कार्यक्रम होने है। राज्य सरकार भी पहली बार शासन के स्तर पर रविन्द्र भवन में कार्यक्रम होगा। प्रदेश अध्यक्ष शाम को बैतूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कश्मीर का जो मामला था उसे उन्होंने हमेशा उठाया और वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसे हल करने का काम किया है। डॉ मुखर्जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उनको नमन करता हूं।

राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी

अर्जेंटीना में भी गूंजा मोदी-मोदी

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के तीसरे चरण में शनिवार को दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना पहुंचे हैं। पीएम मोदी अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इनमें रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, अक्षय ऊर्जा, व्यापार और निवेश आदि क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर इस देश का दौरा कर रहे हैं। कई फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। अर्जेंटीना में पीएम मोदी का स्वागत भारत माता की जय, जय श्री राम के उदघोष के साथ हुआ। प्रधानमंत्री ब्यूनस आयर्स के होटल पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डे सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद पीएम मोदी के सम्मान में देश के राष्ट्रपति माइली दोपहर के भोज की मेजबानी भी करेंगे।

राष्ट्रपति के साथ व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे

राष्ट्रपति माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों सहित कई प्रमुख क्षेत्रों पर भी बात किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में बेहद घनिष्ठ संबंध हैं। वर्ष 2019 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। दोनों देशों ने 2024 में राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। अर्जेंटीना में योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन काफी लोकप्रिय हैं।

57 साल में अर्जेंटीना की पहली यात्रा

यह 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम के रूप में यह मोदी की दूसरी यात्रा है, इससे पहले वह 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए अर्जेंटीना आए थे। भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल पहुंचने पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने समुदाय के लोगों के साथ कुछ देर बातचीत भी की। उनके स्वागत में एक सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया।

यह जीवन बदल देने वाला अनुभव था

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देने वाली कलाकार ज़िनिया ने बताया, यह जीवन बदल देने वाला अनुभव था। हमने भारतीय नृत्य शैलियों को प्रस्तुत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बहुत मेहनत की। मुझे वाकई खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आनंद लिया। वह हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे, और उन्होंने हमें बधाई भी दी भारतीय मूल के अखिलेश वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा।

400 किमी दूर से आकर पीएम से हाथ मिलाया

अर्जेंटीना में एक भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा की। उनकी यह मेहनत सफल रही और उन्हें पीएम के साथ हाथ मिलाने का अवसर भी मिला। अर्जेंटीना में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य विजय कुमार गुप्ता ने एएनआई को अपनी लंबी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं रोसारियो से आया हूं, जो यहां से 400 किलोमीटर दूर है।

सहकारिता दिवस पर मोहन का संबोधन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समन्वय भवन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभागिय मंत्री विश्वास सारंग एवं सहकारिता के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

आरएसएस ने 1962 की जंग को किया याद

स्वयंसेवकों को आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाएगा तैयार

पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार पर किया चिंतन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुक्रवार से दिल्ली में आरंभ हुई। इस बैठक में संघ ने आपातकालीन परिस्थितियों, विशेषकर युद्ध जैसी स्थितियों में स्वयंसेवकों की भूमिका, सिविल डिफेंस अभ्यास (जैसे ऑपरेशन सिंदूर) में भागीदारी और बंगाल व बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गंभीर विचार किया। इस बैठक में ऐसे परिदृश्यों पर चर्चा की जिनमें स्वयंसेवक युद्धकालीन स्थितियों या नागरिक आपदा प्रबंधन अभियानों में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। संघ के प्रचार

प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि संगठन ने अतीत में भी संकट के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री नेहरू के अनुरोध पर दिल्ली में यातायात नियंत्रित किया और राहत सामग्री पहुंचाई थी।

संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की

बैठक में एक अन्य मुख्य मुद्दा रहा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार। संघ के प्रचारकों ने चिंता जताई कि इन घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैठक में इस विषय को सरकार और अन्य मंचों के समक्ष प्रभावशाली रूप से उठाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में अब तक हुए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी वर्षभर चलने वाले अभियानों की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल विजयादशमी पर आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विजय दशमी दो अक्टूबर को है इसलिए आरएसएस इस दिन से अपने शताब्दी वर्ष समारोहों की शुरुआत करेगा। संघ देशभर में सामाजिक समरसता बैठकें और जनसंपर्क अभियान आयोजित करेगा, ताकि समाज के सभी वर्गों में संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

अंतराराष्ट्रीय सहकारी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया संबोधित

सहकारिता को मिलेंगे नए आयाम: मुख्यमंत्री

भोपाल। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं। जीवित जगत के आपस में स्वावलंबन का समावेश ही सहकारिता है। प्रदेश में होने वाले नए कार्यों में सहकारिता समितियों को मिलेगी प्राथमिकता। सहकारिता युवाओं को बेरोजगारी से बचाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का युवाओं को मूल मंत्र- सहकारिता में आने का एक सूत्र है। जब भी कोई नया काम करें तो आत्मविश्वास मजबूत रखें और जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पहले उसका अनुभव लें। सहकारी समिति में क्या-क्या हो सकता है? पहले इसका अध्ययन करें। सहकारी समिति के नेतृत्वकर्ता का दायित्व है कि पहले वह खुद पूरी जानकारी रखें और दूसरे साथियों को भी बताएं। वर्तमान सरकार में सहकारिता को लेकर व्यवस्था पारदर्शी है, और 30 दिन में नई समिति का पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण हो रही है।

आज सीएम ग्वालियर में, 281.71 करोड़ का करेंगे शुभारंभ

ग्वालियर। ग्वालियर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं। सीएम भोपाल से और केन्द्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएंगे। वे 281.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्य व योजनाओं का लोकार्पण-भूमिपूजन कर शहर वासियों को सौगात देंगे। यह कार्यक्रम ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह तथा सांसद भारत सिंह कुशवाह की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया और कमियां पूरी कराईं।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर बदल रहा है और निरंतर विकास के पथ पर चल रहा है। विकसित, समृद्ध होते ग्वालियर की इस प्रगति यात्रा में शनिवार को हजीरा थाने के पास बिरला नगर ग्वालियर में अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद भारत सिंह कुशवाह की मौजूदगी में 281.81 करोड़ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्म दिवस पर मालवीय नगर स्थित उनके कार्यालय पहुंच कर शुभकामनाएं दीं।

भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भक्तों का सैलाब

पुरी/नईदिल्ली, एजेंसी। भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा या वापसी रथ उत्सव शनिवार को औपचारिक पहांडी रस्म के साथ शुरू हुआ। इस दौरान मूर्तियों को श्री गुंडिचा मंदिर से सारधाबली में खड़े रथों तक औपचारिक जुलूस के रूप में ले जाया गया।अधिकारियों ने बताया कि बाहुड़ा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहांडी रस्म दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन यह सुबह 10.30 बजे शुरू हुई, जिसके दौरान त्रिदेवों- भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को एक-एक करके रथों तक ले जाया गया। भव्य रथों - तलध्वज (बलभद्र), दर्पदलन (सुभद्रा) और नंदीघोष (जगन्नाथ) को श्रद्धालु श्री गुंडिचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के मुख्य स्थान, 12वीं शताब्दी के मंदिर तक खींचकर ले जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 2.6 किलोमीटर है।

गौरतलब है कि 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई थी। इसके दो दिन बाद 29 जून को गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। इस भगदड़ को ध्यान में रखते हुए बहुड़ा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बहुदा यात्रा के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं।

मंगला आरती और मैलम जैसे अनुष्ठान किए गए

घंटों और शंखों और झांझों की ध्वनि के बीच सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन को श्री गुंडिचा मंदिर से बाहर निकाला गया और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ पर बैठाया गया। श्री सुदर्शन भगवान विष्णु का चक्र अस्त्र है, जिनकी पूजा पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में की जाती है। श्री सुदर्शन के पीछे भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई भगवान बलभद्र थे। भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा को सेवकों द्वारा सूर्य पहांडी नामक विशेष जुलूस में उनके दर्पदलन रथ पर लाया गया।

पुलिस के 6000 और सीएपीएफ के 800 जवान तैनात

एक अधिकारी के अनुसार, मंदिर शहर में पुलिस के 6,000 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 800 जवान तैनात किए गए हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगदड़ जैसी कोई घटना दोबारा न हो। उन्होंने बताया कि मौसम अनुकूल होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके चलते विशेष यातायात व्यवस्था भी की गई है।

275 सीसीटीवी कैमरे भीड़ और शरारती तत्वों पर रखेंगे नजर

अधिकारी ने बताया कि भीड़ और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए 275 से अधिक एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीजीपी वाईबी खुरानिया खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तटीय शहर पुरी में मौजूद हैं, ताकि बहुड़ा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। खुरानिया ने संवाददाताओं से कहा, हमने त्योहार को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं।

दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा पर सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो माओवादी हुए ढेर

बीजापुर एजेंसी। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा से लगे इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच एक बार मुठभेड़ हुई है। शनिवार सुबह से जारी मुठभेड़ में दो माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का संयुक्त बल क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान पर निकला था। इसी दौरान इंद्रावती नेशनल पार्क के सुदूरवर्ती इलाके में माओवादियों से मुठभेड़ की स्थिति बनी। मुठभेड़ अब भी जारी है और सुरक्षाबल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जंगल के अंदरूनी क्षेत्रों में और भी माओवादियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते आपरेशन को अत्यधिक सतर्कता के साथ अंजाम दिया जा रहा है।

पटौदी परिवार को हाई कोर्ट का झटका

पुश्तैनी संपत्ति विवाद में 25 साल पुराना फैसला पलटा, दोबारा सुनवाई का आदेश

सांध्य प्रकाश संवाददाता

भोपाल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मुहम्मद हमीदुल्लाह खान की पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में पटौदी परिवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वर्ष 2000 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। यह विवाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है, जिसका असर सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, सबा सुल्तान, और सोहा अली खान सहित पटौदी परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ सकता है। हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने अपने फैसले में कहा कि भोपाल के जिला न्यायालय ने वर्ष 2000 में संपत्ति बंटवारे का याचिका का खारिज करते समय कानूनी सिद्धांतों और मुस्लिम पर्सनल लॉ का सही ढंग से पालन नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले (तलत फातिमा हसन मामले) पर आधारित निर्णय लिया, जो अब लागू नहीं है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक वर्ष के भीतर मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बंटवारे पर फैसला देने का निर्देश दिया।

विवाद का इतिहास–यह मामला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मुहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति से जुड़ा है, जिनका निधन 1960 में हुआ था। उनके निधन के बाद उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को संपत्ति की उत्तराधिकारी माना गया था, जो सैफ अली खान की दादी थीं। हालांकि, नवाब की अन्य बेटियों और उत्तराधिकारियों, जैसे सुरैया रशीद और राबिया सुल्तान, ने दावा किया कि संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए। वर्ष 1999 में दायर दो सिविल मुकदमों में संपत्ति के बंटवारे, कब्जे और हिसाब-किताब की मांग की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 2000 में खारिज कर दिया था।

पटौदी परिवार की संपत्ति पर खतरा– पटौदी परिवार की भोपाल और रायसेन में हजारों एकड़ जमीन और ऐतिहासिक संपत्तियां, जैसे फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबाह पैलेस, दर-उस-सलाम, अहमदाबाद पैलेस, और कोहेफिजा प्रॉपर्टी, इस विवाद का हिस्सा हैं। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 15,000 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों को 2014 में 'शत्रु संपत्ति' घोषित किया था, क्योंकि नवाब की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं। सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर ने 2015 में इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने संपत्ति बंटवारे के मामले को नया मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नवाब की निजी संपत्तियां रियासत के सिंहासन से स्वतंत्र हैं और इनका बंटवारा उत्तराधिकार के निजी कानून के तहत होना चाहिए। इस फैसले से सैफ अली खान और उनके परिवार की संपत्ति पर दावा कमजोर हो सकता है, क्योंकि अन्य वारिसों के दावों को भी मान्यता मिल सकती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा 'शत्रु संपत्ति' के तहत संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे भोपाल और रायसेन में रहने वाले करीब 1.5 लाख निवासियों पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है।

रोटरी क्लब ऑफ भोपाल शौर्य का अधिष्ठापन समारोह

भोपाल। रोटरी क्लब ऑफ भोपाल शौर्य का अधिष्ठापन समारोह दिनांक 3 जुलाई, गुरुवार को शाम 8ः00 बजे उपरांत सेलीब्रेशन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटे सुशील मल्होत्रा मंडल 3040 के मंडलाध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं रोटे रूबी मल्होत्रा , मंडल प्रथम महिला, रोटे मुकेश साहू, मंडलाध्यक्ष मनोनीत विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए ।

रोटे शिल्पा मिश्रा, निवर्तमान अध्यक्ष ने गत रोटरी वर्ष 24-25 में की गई रोटरी गतिविधियों और उपलब्धियों से सबको अवगत कराया। रोटे निर्विकार यादव, नव निर्वाचित अध्यक्ष 25-26 ने अपने संबोधन में रोटरी वर्ष के लिये अपना विजन और मिशन शेयर किया । रोटे निर्विकार यादव, अध्यक्ष और रोटे जगजीत सिंह मक्कड़ , सचिव के साथ क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लब निदेशक एवं क्लब कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है । रोटे मुकेश साहू, मंडलाध्यक्ष मनोनीत अधिष्ठापन अधिकारी एवं शपथ ग्रहण अधिकारी ने नवगठीत टीम को रोटरी संकल्प के साथ शपथ दिलाई । रोटे सुशील मल्होत्रा मंडलाध्यक्ष 3040 एवं मुख्य अतिथि ने रोटरी की महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर उड़ते हैं, हम साथ मिलकर सेवा करते है इस थीम पर टीम के सदस्य के रूप में एक साथ मिलकर मानवता की सेवा के प्रति उत्साह, समर्पण और सेवा भावना से आगे बढ़ना होगा । 11 नये सदस्यों को सम्मानित किया और रोटरी की सदस्यता दिलाई गई । तत्पश्चात् राष्ट्रीय गान गाकर कार्क्रम को समाप्त घोषित किया गया। कार्यक्रम में सदस्यों की विशाल उपस्थिति ने क्लब की गरिमा को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर पूर्व मंडलाध्यक्ष आलोक बिल्लौरे धीरन दत्ता कर्नल महेंद्र मिश्रा जिनेंद्र जैन मंडल पदाधिकारी एवम भोपाल के अन्य रोटरी क्लब के अध्यक्ष सचिव भी उपस्थित रहे।

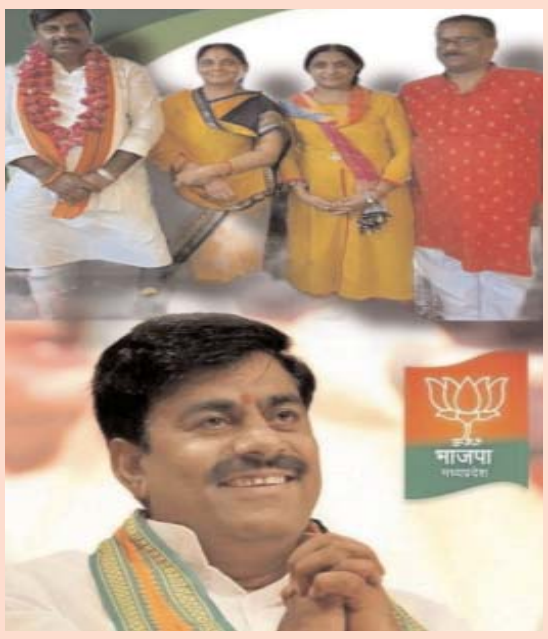

जन्मदिन विशेष

सुदिनं सुदिनं तव जन्मदिनं,
भवतु मंगलं तव जन्मदिनं।।
चिरंजीव, कुरु पुण्यवर्धनं,
सुखं जीव, कुरु कीर्तिवर्धनं। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा,
जगति भवतु तव सुयशोगानं।।
सुदिनं सुदिनं तव जन्मदिनं,
भवतु मंगलं तव जन्म दिनं।।

सनातनी धर्म के ध्वज वाहक सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवम आध्यात्मिक चेतना अग्रदूत सनातनी भक्त... लोकप्रिय जननायक - हूजूर के विधायक संस्था के मार्गदर्शक भाई रामेश्वर जी शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना मंगलकामना करते हैं– प्रभु आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य,यश,कीर्ति,वैभव रूपी पुष्प सदैव सुगन्धित रखें एवं माता वैष्णो देवी अपना आशीर्वाद बनाए रखें
पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं...!!
जय माता दी

सेवादार मण्डल परिवार
श्री वैष्णो देवी भक्त सेवा समिति

गुरु पूर्णिमा पर लाफ्टर शेफ्स' को आशीर्वाद देने एकत्र हुए देशभर के प्रतिष्ठित पंडित

भोपाल। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कलर्स के शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के सेट पर एक अनोखा और भावुक क्षण देखने को मिला, जब देशभर के नौ प्रतिष्ठित पंडितों ने अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से शो को विशेष बना दिया। गुरुजनों को समर्पित शो ने अपने मूल भाव–हंसी, हलचल और सांस्कृतिक श्रद्धा–का खूबसूरती से संगम किया और भारतीय टेलीविजन पर एक यादगार पल रच दिया। एपिसोड की विशेष झलक ब्राह्मण भोज रही – एक पारंपरिक भोज, जिसे सेलिब्रिटी शेफ्स ने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ पंडितों को परोसा। यह केवल एक भोज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कृतज्ञता का प्रतीक था।

इस खास मौके पर भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली, जहां परंपरा और हास्य एक साथ चलते हैं। पंडितों ने न केवल शो को आशीर्वाद दिया, बल्कि शेफ्स के साथ हंसी-मजाक, आत्मीयता और व्यंग्य में भी भागीदारी की। यह

एपिसोड इस बात की याद दिलाता है कि चाहे बात किचन की हो या पंचलाइन की – भारत अपनी आध्यात्मिक जड़ों से कभी नहीं भटकता।

हर पंडित अपने साथ केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि अपने-अपने क्षेत्र की आध्यात्मिक गहराई और ज्ञान लेकर आए थे। काशी के पावन घाटों से पंडित वेंकटेश मिश्रा और काशी विश्वनाथ मंदिर की पारंपरिक गरिमा के संरक्षक पंडित कृष्ण आचार्य पधारे। नर्मदा के किनारे बसे ओंकारेश्वर से पंडित जयेश दीक्षित पधारे– जिनकी शांत और संयमित उपस्थिति ने उनके आध्यात्मिक निवास की शांति के दर्शन कराए।

आयुषमान भारत योजना से जुड़वा भाईयों के सेवा सदन में मोतियाबिंद के सफल आपरेशन हुए

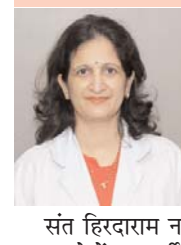

वरिष्ठ बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रश्मि आप्टे ने किया सफल आपरेशन

संत हिरदाराम नगर। रेहटी निवासी कृषक अजय कुमार रावल के जुड़वा बेटों 14 वर्षीय समर और समर्थ को जन्म से ही देखने में दिक्कत होती थी। दोनों बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गये उनकी दोनों आंखों में नज़र कमजोर होने लगी और उनको अपने सामान्य कामकाज के साथ ही पढ़ाई-लिखाई में भी तकलीफ होने लगी। माता पिता ने बच्चों के शैशव काल में बहुत अस्पतालों में जाकर शिशुओं का इलाज करवाया, लेकिन सभी अस्पतालों में उन्हें यह कहा गया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। छः महीने पहले तो दोनों बच्चों की आंखें भी सफेद होने लगी, इससे माता पिता की परेशानियां और बढ़ गई थी दोनों जुड़वा भाइयों को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस बीच किसी परिचित ने उन्हें बच्चों को संत हिरदाराम नगर भोपाल स्थित सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय की वरिष्ठ बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रश्मि आप्टे को दिखाने के लिये कहा।

14 साल के जुड़वा भाई समर और समर्थ भी अब पढ़ाई के साथ-साथ देख सकेंगे दुनिया

समर और समर्थ के माता पिता बच्चों को गुरूवार 26 जून को सेवा सदन लेकर आये और डॉ. रश्मि आप्टे ने इन दोनों बच्चों की आंखों का परीक्षण किया। डॉ. आप्टे ने 30 जून को समर और समर्थ की एक-एक आंख का मोतियाबिंद का आपरेशन किया। दोनों बच्चों के ऑपरेषन आयुषमान भारत योजना के अन्तर्गत किये गये, जिसमें अभिभावकों का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। अगले दिन पट्टी खुलने पर दोनों बच्चों और उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये दोनों बच्चे फिर से प्रभु की सुंदर संरचना सृष्टि को निहारने लगे हैं। बच्चों के अभिभावकों ने डॉ. रश्मि आप्टे, सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, राज्य और केन्द्र सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा प्रथम, रायसेन द्वितीय और बालाघाट तृतीय स्थान पर

भोपाल। जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले खंडवा जिले ने प्रथम स्थान, रायसेन द्वितीय और बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा शुक्रवार को जिला व जनपद स्तरीय पुरस्कार की सूची जारी की है। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों की रैंकिंग सूची में जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा जिले ने 92.50 प्रतिशत, रायसेन जिले ने 92.35 प्रतिशत और बालाघाट जिले ने 87.56 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत-तालाब के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य वाले जिले को पुरस्कार देने के लिए ÷ए÷ तथा ÷बी÷ दो श्रेणियां बनाई गई थी। ÷ए÷ श्रेणी में 4 या उससे कम जनपदों को शामिल किया गया था, जबकि बी श्रेणी में 5 या उससे अधिक जनपदों को शामिल किया गया था। शुक्रवार को जारी सूची में ÷ए÷ श्रेणी जिसमें 4 या उससे कम जनपद है, उसमें अनूपपुर जिला व बी श्रेणी जिसमें 5 या इससे अधिक जनपद है, उसमें बालाघाट जिले ने अपना स्थान बनाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत-तालाब के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य वाली जनपद पंचायतों को विकासखंड स्तर पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।

कला लक्ष्मणदास एवं केवलराम पब्लिक स्कूल में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन

संत हिरदाराम नगर। शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित कला लक्ष्मणदास वेंसीमल गनवानी फाउंडेशन स्कूल एवं केवलराम चैनराय पब्लिक स्कूल में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ, जिसमें सिद्ध भाऊ, सोसायटी के सचिव घनश्याम बूलचंदानी एवं विद्यालय की प्राचार्या सुमन विश्वकर्मा उपस्थित थे। विद्यालय के कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के मेधावी छात्रों को इस अवसर पर सिद्ध भाऊ के कर-कमलों से प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।सिद्ध भाऊ ने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए नियमित पढ़ाई, योग और सूर्य नमस्कार को जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठोर मेहनत से सफलता हासिल की, वैसे ही आज के विद्यार्थी भी अनुशासन और समर्पण से ऊँचाइयाँ छू सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्याधन को कोई चुरा नहीं सकता, अतः इसे अर्जित करें और समयबद्ध जीवनशैली अपनाएँ।

फसल की सुरक्षा के लिये खेत पर तार-फेंसिंग लगाने का आधा खर्च सरकार वहन करेगी

भोपाल। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों पर तार-फेंसिंग लगाने का आधा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। अब राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत उद्यानकी फसल उगाने वाले कृषक अपने खेत के चारो ओर 5 तार व खम्बे की फेंसिंग लगवा सकते हैं। उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। विभाग द्वारा जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। आयुक्त उद्यानकी के अनुसार उद्यानकी फसलों में सब्जी, फल, फूल एवं मसालों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है। इससे बचाव के लिये यह योजना लागू की गई है। विभाग द्वारा किसानों को तार-फेंसिंग लगाने में आने वाला खर्च का आधा (50 प्रतिशत) अनुदान प्रदान किया जाएगा। तार-फेंसिंग लगाने का खर्चा 300 रुपये प्रति रनिंग मीटर आता है, यानि एक हजार रनिंग मीटर का खर्चा तीन लाख रुपये है। इसमें डेढ़ लाख रुपये राज्य सरकार देगी तथा शेष डेढ़ लाख रूपये किसान वहन करेगा।

स्कूलों में गुरू पूर्णिमा पर होगा दो दिवसीय उत्सव

भोपाल। प्रदेश के सभी विद्यालयों में 10 जुलाई गुरूवार को गुरू पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन 9 और 10 जुलाई को होगा। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि पहले दिन 9 जुलाई को विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों द्वारा गुरू पूर्णिमा के महत्व और पारंपरिक गुरू-शिष्य संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जायेगी। विद्यालय में प्राचीन काल में प्रचलित गुरूकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति में प्रभाव विषय पर बच्चों के बीच में निबंध लेखन प्रतियोगिता की जायेगी। विद्यालयों के प्राचार्यों से कहा गया है कि आयोजन के दौरान साधु-संतों, गुरूजनों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, विद्यार्थियों और नागरिकों को आमंत्रित किया जाये। इन आयोजन में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। पूर्व विद्यार्थी अपने शाला जीवन के अनुभव को विद्यार्थियों के बीच साझा करेंगे।उत्सव के दूसरे दिन 10 जुलाई को गुरू पूर्णिमा के दिन प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में वीणा वादिनी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर गुरू वंदना की जायेगी। विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरू की महिमा पर केन्द्रित व्याख्यान होंगे। इसी के साथ इस दिन गुरूजनों एवं शिक्षकों का सम्मान भी किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों में भारतीय मूल्यों संस्कृति आधारित शिक्षा के लिये कई उल्लेखनीय कदम उठाये गये हैं। उनमें से एक विद्यालयों में गुरू पूर्णिमा का आयोजन किया जाना भी एक है।

जीपीएफ गुमशुदा कटौत्रों के निराकरण के लिये भोपाल में विशेष शिविर 7 से 11 जुलाई तक

भोपाल। प्रधान महालेखाकार द्वितिय द्वारा भोपाल में सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा कटौत्रों से संबंधित समस्याओं के निराकरण और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भोपाल के तीन प्रमुख कोषालयों- जिला कोषालय, विंध्याचल कोषालय एवं वल्लभ भवन कोषालय में 7 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक विशेष शिविर (कैंप) आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर विंध्याचल भवन तृतीय तल यूनएडीपी हॉल में निर्धारित किया गया है। महालेखाकार दल द्वारा शिविर में अभिदाताओं के समक्ष चर्चा कर समस्या का समाधान किया जायेगा। अभिदाताओं को विसंगतियों के समाधान के लिये वांछित दस्तावेज लाना होगा। यह शिविर सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल गुमशुदा जीपीएफ कटौत्रों की समस्याओं का समाधान होगा।, बल्कि भविष्य निधि से जुड़े अंतिम भुगतान प्रकरणों में बरती जाने वाली सावधानियों, आवश्यक प्रपत्रों, और पत्राचार की प्रक्रिया को लेकर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन श्री राजीव सिंह पवैया ने बताया कि सभी अधीनस्थ तीनों कोषालयों से समन्वय करते हुए प्रशासन ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सभी आहरण संवितरण अधिकारी को पंपलेट्स के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। शिविर स्थल पर कम से कम 150 अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था, बिजली, पानी, लैपटॉप-प्रिंटर के लिए तकनीकी सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस शिविर से लाभान्वित हों, जिससे उनके सामान्य भविष्य निधि खातों से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके।

संस्कार विद्यालय के होनहार विद्यार्थी का सेना में अधिकारी पद पर चयनित होने पर सम्मान

संत हिरदाराम नगर। दीपमाला पागारानी संस्कार विद्यालय के होनहार विद्यार्थी कुमार गौतम भम्भानी का सेना में अधिकारी पद पर चयनित होने पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव बसंत चेलानी ने कुमार गौतम भम्भानी को बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे विद्यालय के सत्र 2023-24 के होनहार विद्यार्थी कुमार गौतम भम्भानी का सब लैफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है इसने बचपन में संकल्प लिया था कि मुझे सेना में भर्ती होना है। इसका आर्मी और नेवी दोनों में चयन हुआ है। गौतम को यह सफलता परिश्रम और अथक प्रयास करके प्राप्त हुई है।

कार्यक्रम में उपस्थित कर्नल नारायण पारवानी ने गौतम भम्भानी को बधाई देते हुए कहा कि गौतम का जिस पद पर चयन हुआ है उस परीक्षा को पास करना कोई आसान काम नहीं बल्कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपने अथक प्रयास से उसने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि बहुत कम बच्चें है, जो सेना में उच्च पदों पर चयनित होते है, जो बच्चा शुरू से एक लक्ष्य निर्धारित करता है उसको सफलता अवष्य मिलती है, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते है उसको तय करों और उस पर फोकस करों, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संस्था के अध्यक्ष सुशील वासवानी ने गौतम भम्भानी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के कोषाध्यक्ष चन्दर नागदेव ने गौतम भम्भानी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कुमार गौतम भम्भानी ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि मैंने कक्षा नर्सरी से 12वीं तक इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है मेरी सफलता में स्कूल और शिक्षिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है मैं इस परीक्षा में पहले तीन बार फैल हुआ, लेकिन लगातार प्रयास से मैने सफलता प्राप्त की।

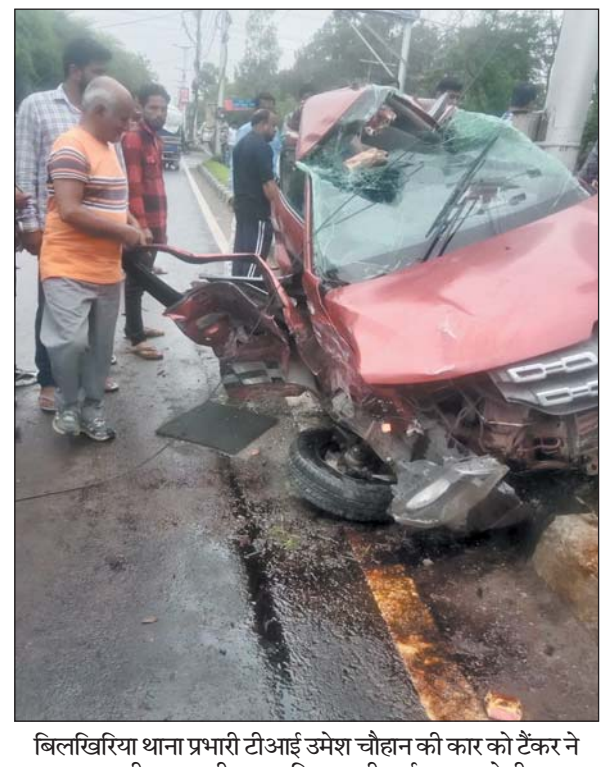

बिलखिरिया थाना प्रभारी टीआई उमेश चौहान की कार को टैंकर ने टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, टीआई साहब को पीपुल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सरई में हुआ महिला सशक्तीकरण एवं जनजातीय गौरव सम्मेलन

दीपावली के बाद बहनों को हर महीने देंगे 15 सौ रुपए :मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंगरौली प्रदेश का सीमावर्ती, खनिज सम्पन्न और सर्वप्रिय जिला है। सिंगरौली को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। अगले साल से यहां पढ़-लिखकर डॉक्टर निकलेंगे। आज प्रदेशभर के 94 हजार 234 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर की गई है। इसमें 60 प्रतिशत छात्राएं और 40 प्रतिशत छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार जनजातीय अंचल में सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बीते 2 साल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 15 हजार से अधिक स्कूटी बांटी गई हैं। हमारी सरकार सबके चतुर्दिक विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को सिंगरौली जिले के सरई गांव में महिला सशक्तिकरण तथा जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 503 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 54 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कुछ दिनों बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल सहित बच्चों की सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों का एक साथ लोकार्पण होगा। शासकीय स्कूलों के बच्चों को साइकिल, ड्रेस और किताबों का वितरण भी किया जाएगा। भागवत गीता से मध्यप्रदेश का संबंध है। वृंदावन ग्राम बनाकर भगवान श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता को जीवंत करना है। बच्चे पढ़ाई करके कहीं भी जाएं, पर अपने गरीब मित्र को न भूलें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय गौरव सम्मेलन में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय वर्ग के चार व्यक्तियों महाबली सिंह, शंकर सिंह पनिका, वंश बहादुर सिंह और दयाल सिंह का मंच से सम्मान किया।

सिंगरौली को जल्द मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात

कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री तथा सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह, क्षेत्रीय सांसद राजेश मिश्रा, विधायक राजेंद्र मेश्राम, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, विधायक विश्ममित्र पाठक सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के कार्यक्रम विक्रमोत्सव 2025 को मिला एशिया का वाउ गोल्ड अवार्ड

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को वाउ अवार्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। WOW Awards Asia की टीम भोपाल आकर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यह अवार्ड प्रदान करेंगी। विगत वर्ष विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिल चुका है। विक्रमोत्सव 2025 को यह सम्मान मिलने पर माननीय मुख्यमंत्रीजी के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने इसे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संस्कृति और विरासत के प्रति उनके समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव 2025 को प्राप्त यह सम्मान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। विक्रमोत्सव एक आयोजन मात्र नहीं है बल्कि इन सबसे बढ़कर संस्कृति, विरासत और विकास का बेजोड़ संगम हैं। बीते 18 वर्षों से निरंतर विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है।

विगम वर्षों में विक्रमोत्सव ने देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी उत्सवधर्मी पहचान को बखूबी स्थानपित किया है। इसमें ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि WOW Awards Asia, वर्ष 2009 से लाइव इवेंट्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रतिष्ठित मंच रहा है। यह आयोजन अनुभव आधारित विपणन, व्यापारिक बैठकों, प्रोत्साहन यात्राओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सजीव मनोरंजन तथा विवाह उद्योग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और आयोजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान करता है। इस वर्ष इसका 16वाँ संस्करण, दिनांक 20 और 21 जून 2025 को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सहभागिता की।

प्रधानमंत्री कर चुके है सराहना

विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के गौरव और वैभव को जन-जन तक पहुँचाने का यह प्रयास सराहनीय है। उनका शासन काल जन-कल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। मध्यप्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह आयोजन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़कर आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा की भावना से परिपूर्ण नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

विक्रमोत्सव 2025 में 300 से अधिक गतिविधियां हुई आयोजित

विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 300 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक एवं बहुआयामी गतिविधियाँ सम्पन्न हुई। इस महोत्सव में लाखों लोग भागीदार रहे जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग विक्रमोत्सव से जुड़े। विक्रमोत्सव की बहुआयामी गतिविधियों में मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख शिवरात्रि मेलों का समारंभ, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, वादन, शिवोत्सम, आदि-अनादि पर्व समारोह, विक्रम नाट्य समोराह, चित्र प्रदर्शनियाँ, संगोष्ठी, भारतीय इतिहास समागम, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, वेद अंताक्षरी, कोटि सूर्योपासना, शिल्प कला कार्यशाला, प्रकाशन, विक्रम पंचांग, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बोलियों एवं हिन्दी रचनाओं का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 1000 ड्रोन्स की प्रस्तुति व ख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियाँ शामिल है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शहडोल मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन सेवा का किया शुभारंभ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल में टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवा ग्रामीण, दूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों तक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति जनसामान्य को त्वरित, विशेषज्ञ और सुलभ उपचार प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनेगी।

प्रदेश में स्वैच्छिकता पर्व के रूप में मनाया जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस

भोपाल । मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस शुक्रवार को प्रदेश भर में 'स्वैच्छिकता पर्व' के रूप में मनाया गया। 'संगच्छध्वम संवदध्वम' की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालयों पर विभिन्न आयोजन हुए। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित परिषद के राज्य कार्यालय में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन, परिषद द्वारा निर्मित लघु फिल्मों का प्रदर्शन और स्वैच्छिकता शपथ दिलाई गई।

परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कहा कि परिषद स्वैच्छिकता की भावना के साथ गांव-गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 10-12 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।÷ उन्होंने बताया कि परिषद के पास वर्तमान में साढ़े तीन लाख स्वयंसेवकों का अमला है, जो सरकार और समाज के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में परिषद का नेटवर्क प्रदेश के लगभग 55 हजार गांवों तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने परिषद की आगामी कार्ययोजनाओं और वर्तमान गतिविधियों की भी विस्तृत जानकारी दी।

परिषद के पूर्व महानिदेशक श्री बीआर नायडू ने कहा मैं परिषद की विकास यात्रा का साक्षी रहा हूं।परिषद ने पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अब समय है कि परिषद एक दीर्घकालिक विजन तैयार करे।÷ परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़ ने परिषद के मिशन और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, ÷वर्तमान में परिषद का साढ़े तीन लाख का अमला है, जिसे 35 लाख तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। जल गंगा संवर्धन अभियान में परिषद की भूमिका सराहनीय रही है। समारोह में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप सचिव श्री विकास मिश्रा, गौसेवा समिति के संयोजक श्री विलास राव और सलाहकार श्री करण सिंह ने परिषद की उपलब्धियों और योजनाओं पर अपने विचार साझा किए।

आयोजन में परिषद के पूर्व कार्यपालक निदेशक डॉ. धीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, नर्मदा समग्र के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कार्तिक सप्रे, प्रस्फुटन समितियों व नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, सीएमसीएलडीपी के छात्र और परिषद के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। आयोजन स्वैच्छिकता की भावना को बढ़ावा देने और सामाजिक विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त मंच साबित हुआ। परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब, कांग्रेस लड़ेगी आरपार की लड़ाई

भोपाल। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें लांघ दी हैं। म.प्र. सरकार ने ओ.बी.सी. वर्ग को अपना हक ना मिले इसके लिए संविधान के मूल ढ़ाचा से भी खिलवाड़ कर रहे है। संविधान में यह विदित है कि विधायिका के बनाए हुए कानून को अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है परंतु कार्यपालिका अपने दायित्व को निभाही नहीं रही है माननीय उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को पैरों तले रौंदते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ओबीसी भाइयों-बहनों को उनके 27त्न आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा है, जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है ! बीजेपी की यह साजिश मध्य प्रदेश की 50त्न से अधिक आबादी को गुलाम बनाए रखने और उनके भविष्य को तबाह करने की है यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर ओबीसी को 27 प्रतिशतआरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की थी। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश कर रही है।

कक्षा-6 की पाठ्य पुस्तक एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण

भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र, स?कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की दिशा में सेवाकालीन प्रशिक्षण इन दिनों चल रहा है। यह प्रशिक्षण अकादमिक वर्ष 2025-26 में एनसीईआरटी की कक्षा-6 की नवीन पाठ्य-पुस्तक पर केन्द्रित है।

प्रशिक्षण प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों पर चल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक्सिस बैंक के सीएसआर फण्ड सहयोग से कार्यरत संस्था 'पीपल' द्वारा यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 60 हजार से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में सहभागिता कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण के तहत जून माह में राज्य स्तर पर 36 एसआरजी एवं लगभग 2 हज़ार मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में 60 हजार शिक्षकों की सहभागिता

प्रदान किया जा रहा है, जो जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक जारी रहेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकगण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं राष्ट्रीय पाठयचर्या रूपरेखा स?कूल शिक्षा पर आधारित पाठ्य-पुस्तकों के अध्यापन के लिए उचित शिक्षण विधियां तय कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक नई शिक्षा नीति की मंशानुरूप कक्षा में शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे।

एनसीईआरटी द्वारा सभी बच्चों को उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कक्षा-6 की गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की नवीन पुस्तकें तैयार की गई हैं। इन पुस्तकों को प्रदेश में इस अकादमिक वर्ष से क्रियान्वयन में लाया जा रहा है।

मंत्री भूरिया से मिली चैम्पियन बालिकाएं

बालिका गृह की बेटियों ने जीता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

भोपाल के बालिका गृह की कुछ खास बच्चियाँ गौरव की प्रतीक बन गई हैं। इन बच्चियों ने 'फर्स्ट एशियन चेस फॉर फ्रीडम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।

शुक्रवार को इन चैम्पियन बच्चियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया से मुलाकात की, तो माहौल भावनाओं से भर गया। आँखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और मन में कुछ कर दिखाने की आग, हर बच्ची की मुस्कान एक नई कहानी कह रही थी। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बच्चियों को बधाई दी और कहा कि ये सिर्फ

एक जीत नहीं, ये समाज के लिए एक संदेश है कि हर बच्ची, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में जन्मी हो, अगर उसे अवसर मिले तो वह सितारों को छू सकती है। उन्होंने बच्चियों का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि यह भी भरोसा दिलाया कि उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। सुश्री भूरिया ने कहा कि ये बेटियाँ अब सिर्फ बालिका गृह की बच्चियाँ नहीं रहीं। अब वे प्रेरणा बन चुकी हैं, उन लाखों बच्चों के लिए, जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारुकी वली ने कहा कि इन बच्चों को प्रोत्साहन देना, इनका सबसे बड़ा सम्मान है। मिशन वात्सल्य की टीम के मोटिवेशन के साथ इन बच्चियों ने लगन और मेहनत से ये अपार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बच्चियों को बधाई देते हुए कहा कि आपने जीवन की निराशा को आशा में बदलकर अपने भविष्य को गढ़ा है।

उल्लेखनीय है कि वीएसटी एशियन चेस फॉर फ्रीडम चैंपियनशिप ऑनलाइन चैंपियनशिप है। इसमें चार महाद्वीपों के 15 देशों ने भाग लिया। इंडियन ऑयल की परिवर्तन प्रिजन टू प्राइम के तहत इन बच्चियों को चेस खेल का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक अभिजीत कुंटे ने बताया कि पहली बार जब मैं इन बच्चियों को प्रशिक्षण देने गया तो सब डरी सहमी थी, पर इनके जज्बे को सलाम है। इनकी लगातार 3-6 महीने की मेहनत ने इन्हें चैंपियन बना दिया है। श्री कुंटे ने कहा कि अब बालिकाएं अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग ने किया राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय राज्य स्तरीय चयन इंटरव्यू कार्यक्रम का आयोजन भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया गया। इस विशेष आयोजन में महेंद्र जोशी (प्रदेश प्रभारी प्रशिक्षण), विंग कमांडर अनुमा आचार्य, निधि चतुर्वेदी, ललित सेन, आनंद जाट, अवनीश भार्गव एवं इरफ़ान खान सहित अनेक वरिष्ठ प्रशिक्षण विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। इस इंटरव्यू में प्रदेश के 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें से 100 प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षकों को आगामी दो दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका आयोजन इसी माह पीसीसी में किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सभी प्रशिक्षकों को जिले अलॉट किए जाएंगे, जहाँ वे बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह संपूर्ण प्रशिक्षण अभियान अगले दो वर्षों तक सघन रूप से चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, वैचारिक स्पष्टता एवं बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं में दक्षता का विकास करना है। इस संदर्भ में संगठन महामंत्री डॉ संजय कामले ने कहा यह प्रशिक्षण अभियान कांग्रेस पार्टी के पुनर्गठन, सशक्तीकरण और विचारधारा के प्रसार का मजबूत माध्यम बनेगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर हम जमीनी स्तर पर एक संगठित, सशक्त और वैचारिक रूप से स्पष्ट नेतृत्व तैयार करेंगे। यह प्रशिक्षण पहल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है, जो कांग्रेस संगठन को हर स्तर पर सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी से एमबीबीएस कोर्स की सराहना की

भोपाल। संसदीय राजभाषा समिति ने मध्यप्रदेश में हिंदी माध्यम से संचालित चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की सराहना की है। समिति ने इस पहल को भारतीय भाषाओं में तकनीकी व उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस कदम बताया और सुदृढ़ीकरण के लिए सुझाव दिए। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब (सांसद, लोकसभा, कटक - ओडिशा) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सम्पन्न हुई। समिति ने संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों से संवाद कर हिंदी माध्यम में अध्ययन से जुड़े अनुभव एवं पुस्तकों की गुणवत्ता पर फीडबैक प्राप्त किया। समिति ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक स्तर पर आने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सतत निगरानी, चरणबद्ध समीक्षा तथा फीडबैक आधारित सुधारात्मक पहल अपनाई जानी चाहिए। बैठक में संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य उज्ज्वल रमण सिंह (सांसद, लोकसभा, इलाहाबाद - उत्तर प्रदेश), शंकर लालवानी (सांसद, लोकसभा,

इंदौर - मध्यप्रदेश), डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी (सांसद, राज्यसभा, मध्यप्रदेश), डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे (सांसद, राज्यसभा, महाराष्ट्र), हरिभाई पटेल (सांसद, लोकसभा, मेहसाणा - गुजरात), कुलदीप इंदौरा (सांसद, लोकसभा, गंगानगर - राजस्थान) और जियाउर्रहमान (सांसद, लोकसभा, संभल - उत्तर प्रदेश) उपस्थित रहे। समिति सचिव प्रेमनारायण, हिंदी अधिकारी मनोज कुमार और रिपोर्टर मोहम्मद आरिफ़ भी बैठक में सम्मिलित हुए। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति के अध्यक्ष मयंक अग्रवाल और महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. कविता एन. सिंह ने समिति का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश में हिंदी माध्यम से मेडिकल शिक्षा की प्रगति पर प्रस्तुति दी। बताया गया कि प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सभी 15 विषयों की पुस्तकों का हिंदी में सफलतापूर्वक अनुवाद एवं संपादन किया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भोपाल में की जनसुनवाई

प्रदेश की 32 जातियों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने प्रतिनिधियों ने रखा पक्ष

भोपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर एवं आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल ने आज वीआईपी गेस्ट हाउस में जनसुनवाई की। मामला प्रदेश की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल 32 जातियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने का है। जनसुनवाई के दौरान इन जातियों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित होने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

इन जातियों के प्रतिनिधियों का कहना था कि राष्ट्रीय सूची में नाम शामिल न होने से उनकी जाति के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इस दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया एवं सदस्य सीताराम

यादव के साथ अपर सचिव अनुराग चौधरी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त सौरभ सुमन मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव डॉ. देवेश कुमार मिश्रा भी सुनवाई में शामिल हुए।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव देवेश मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की 32 जातियों को लेकर यह सुनवाई की जा रही है। इस जाति के लोग खुद को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल कराना चाहते हैं। सचिव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मिश्रा ने बताया कि वर्तमान स्थिति में केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में मध्यप्रदेश राज्य के लिए 68 जातियां सम्मिलित हैं।

केंद्रीय सूची में इन जातियों को शामिल करने की मांग

जनसुनवाई में पिछड़ा वर्ग की दवेज, भोपा मनभाव, दमामी, हरिदास, कोहरी, फूलमाली (फूलमारी), कलार, जायसवाल, डउसेना, लोढ़ा (तंवर), गोलान, गौलान, गवलान, जादम, कुडमी, रूआला- रूहेला, अब्बासी के साथ सक्का, घोषी गवली और गोली शामिल हैं। इनके अतिरिक्त लिंगायत, महाकुल (राउत), थारवार, जमना लोधी, मनधाव डूकर, कोल्हाटी, घड़वा, झारिया, वोवरिया, मोवार, रजवार, सुत सारथी, तेलंगा, तिलंगा, गयार- परधनिया, बया महरा- कौशल, वया थोरिया, खरादी, कमलीगर, संतराम, शेख मेहतर के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने अपनी-अपनी जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल करने की मांग की।

संपादकीय

मतदाता सूची सुधार अभियान पर हल्ला क्यों?

देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के क्रम में किसी मजबूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं! मतदाता सूची को त्रुटियों से रहित बनाने का काम निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाने के भी अपने आधार हैं। आयोग की ओर से इस सूची में बने रहने के लिए जिन स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, बिहार के बहुत सारे लोगों को लिए यह एक बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी-खासी होगी, जिनके पास खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे और अगर वे इन्हें नए सिरे से बनवाने के काम में लगेंगे तो इसके लिए समय की जरूरत होगी। जबकि बिहार में अक्तूबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए महज एक माह का समय दिया गया है। स्वाभाविक ही इस समय के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, अगर उसमें शामिल होने के पात्र लोग किन्हीं वजहों से छूट गए, तो उनके दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? यह छिपा नहीं है कि बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसे गरीब और कम शिक्षित लोगों की है, जिनके पास सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होंगे। खासतौर पर जन्म पंजीकरण के मामले में काफी पीछे रहने की वजह से बहुत कम लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं। हालांकि हाशिये के समुदायों के ज्यादातर लोगों की पहुंच आधार और राशन कार्ड तक है, जिनकी मांग आमतौर पर हर चीज के लिए की जाती है। मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से इन्हें स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ताजा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इस दायरे में आएंगे, उनके लिए भी निर्धारित दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा।

सहयोग की शक्ति और सामाजिक समरसता का उत्सव

ललित गर्ग

हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मानित करने का अवसर होता है। सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जो 'एकता में शक्ति' की भावना को मजबूत करता है और लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायसंगत आदर्श समाज के निर्माण में सहायक बनता है। सहयोग की शक्ति और सामाजिक समरसता के इस उत्सव का 2025 की थीम है 'सहकारिताः एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना।' यह थीम पर्यावरण-संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों को सहयोग के माध्यम से हल करने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है, सहकारिता एक वैकल्पिक और मानवीय मॉडल प्रस्तुत करती है। यह न केवल आर्थिक विकास की राह दिखाती है, बल्कि सामाजिक विश्वास, सह-अस्तित्व और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है।

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह 29वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस और 101वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस होगा। यह सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के पूरक लक्ष्यों और उद्देश्यों को उजागर करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में आंदोलन के योगदान को रेखांकित और विस्तारित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 2012 में पहले सफल आयोजन के बाद की गई है और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से न्यायसंगत पुनर्प्राप्ति की पेशकश कर रही हैं।

सहकारिता दिवस इस बात का प्रचार करने का अवसर है कि किस प्रकार मानव-केन्द्रित व्यवसाय मॉडल, जो स्वयं-सहायता और एकजुटता के सहकारी मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व और समुदाय के प्रति चिंता के नैतिक मूल्यों द्वारा समर्थित है, असमानता को कम कर सकता है, साझा समृद्धि का सृजन कर सकता है। सहकारी समितियां, जो आर्थिक सफलता को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव सदस्य देशों को सहकारी समितियों के लिए एक सहायक कानूनी और नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें कृषि, वित्त और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व पर जोर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने इस घोषणा को संगठन के सतत विकास के लिए चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित करने पर प्रकाश डाला। इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर समानतापूर्ण और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने। सहकारिता पर ध्यान केंद्रित करके, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य टिकाऊ, समुदाय-केंद्रित समाधान प्रदान करने में मॉडल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है।

सहकारिता, जिसे अंग्रेजी में कोआपरेटिव कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर काम करते हैं ताकि अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह एक लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित व्यवसाय है जहां सदस्य ही मालिक होते हैं और व्यवसाय का संचालन और लाभ का वितरण भी सदस्यों के बीच ही होता है। सहकारिता का अर्थ है, 'मिलजुल कर काम करना' या 'आपस में सहयोग करना'। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वे अपने सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक हित को बढ़ावा देना है। इसका मूल मंत्र है 'सभी के लिए एक, और एक सभी के लिए।'

भारत में सहकारिता की भावना एवं विचारधारा आजादी से पहले से जन-जन में रची-बसी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुली मिली है, ये कोई उधार लिया विचार नहीं है। सहकारिता भारत के संस्कार में है। भारत में सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। सहकारिता की जड़े 1904 के सहकारी ऋण समितियां अधिनियम से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन और भी सशक्त हुआ। चाहे अमूल जैसी डेयरी सहकारी संस्थाएं हों या सहकारी बैंकों और किसान समितियां, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब सहकारिता आंदोलन की सबसे अधिक जरूरत थी, तब यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहिकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को नये आयाम दिये हैं। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री अपने-अपने राज्यों में कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आम लोगों के साथ-साथ धरती माता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके।

गरीब कल्याण और गरीब उत्थान, बिना सहकारिता के सोचा नहीं जा सकता। नरेन्द्र मोदी के मन की इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है। देश पर जब-जब कोई विपदा आई है, सहकारिता आंदोलनों ने देश को बाहर निकाला है। कॉपरेटिव बैंक बिना मुनाफे की चिंता किए लोगों के लिए काम करते हैं क्योंकि, भारत के संस्कारों में सहकारिता है। आज देश में लगभग 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां छोटी-बड़ी कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है। सहकारिता गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-(एनसीडीसी) और सहकारिता मंत्रालय जैसे संस्थान इस क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की सहकारिता सोच एवं मोदी सरकार की प्रतिबद्धताएं दुनिया के लिये एक प्रेरक मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज को जोड़ने, ऊपर उठाने, संतुलित विकास और ग्रामीण जीवन को टिकाऊ बनाने की क्षमता रखता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि यदि हम साथ मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सहयोग ही सशक्तिकरण की कुंजी है। प

बम भोले के नाम पर?

राकेश दुबे

विश्व प्रसिद्ध कांवड़-यात्रा 11 जुलाई से आरंभ हो रही है। इन सालों में जो सांप्रदायिक तनाव दिखा है, नफरत महसूस की है, कमोबेश 10 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। हालांकि हिंदू-मुसलमान भारतीय राजनीति का शाश्वत भाव रहा है, लेकिन कांवड़-यात्रा के दौरान मुसलमान भी शिव-भक्तों की खूब सेवा करते दिखाई दिए हैं। शिविर लगाए जाते रहे हैं, भोजन परोसा जाता है, मीठा पानी पिलाया जाता है, शिव-भक्तों के जख्मों की प्राथमिक चिकित्सा भी की जाती रही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तुलना पहलगाम के हत्यारे आतंकियों से करने की नौबत आ गई?

उप्र और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी किए हैं कि कांवड़-यात्रा के मार्ग के ढाबे, होटल, रेस्तरां, दुकानदार, खोमचेवाले स्पष्ट नामपट्टिका लगाएंगे। लाइसेंस नंबर भी दिखाएं और पहचान-पत्र रखें। यानी स्पष्ट होना चाहिए कि ढाबे, होटल का मालिक हिंदू है अथवा मुस्लिम है! यह व्यवस्था बीते साल भी लागू की गई थी, ताकि कांवडियों की आस्था और श्रद्धा खंडित न हो। हरिद्वार और ऋषिकेश तक की अक्सर नंगे पांव की यह यात्रा हिंदुओं का बड़ा धार्मिक आयोजन है। जुलाई, 2024 में सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश के साथ सरकार के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत का फैसला था कि नामपट्टिका लगाना जरूरी नहीं है। अलबत्ता यह साफ-साफ लिखा जाना चाहिए कि ढाबे में शाकाहार या मांसाहार क्या उपलब्ध है? कांवड़-यात्री अपने पर्व के अनुसार, शाकाहार वाला ढाबा चुन सकेगा।

अदालत के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए उप्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने इस साल फिर आदेश जारी कर दिए। उसकी आड़ में हिंदू संगठनों के कुछ स्वयंभू हुड़दंगी राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर स्थित एक ढाबे की जांच के लिए आ धमके। दलीलें दी गईं कि वह ढाबा मुस्लिम का था, लेकिन बोर्ड पर लिखा था-'पंडित का शुद्ध वैष्णो ढाबा।' यानी पहचान छिपाने का अपराध किया गया था। आरोप हैं कि हुड़दंगियों ने ढाबे के कर्मचारियों की पैंट उतरवा कर यह जांचने की कोशिश की कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं! विवाद यहीं से भड़का। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि इन और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है? दोनों तरह के आतंकियों ने धर्म की आड़ में कुकर्म किया।

फर्क सिर्फ इतना है कि पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मार दी और हिंदू पर्यटकों की हत्याएं कीं। कांवडियों के पैरोकारों ने पैंट ही उतरवाई थी। उस ढाबे पर यह घटना हुई अथवा उसे 'सांप्रदायिक मोड़' दे दिया गया, यह जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिकी में 6 आरोपितों के नाम हैं। सभी हिंदूवादी संगठनों के बताए जा रहे हैं। इस घटना में एक स्वयंभू बाबा भी कूद पड़े हैं, जो उसी इलाके में योग-साधना सिखाते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि कोई केस बनाया गया, तो देश भर में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। बाबा ने पैंट उतारने की घटना को फर्जी करार दिया है। यहां बेहद गंभीर सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारों की कानून-व्यवस्था बेलगाम और हिंदू दबंगइयों के हाथ है? उप्र देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी झटका लगा था। उसके बाद भाजपा नेता ऑफ दि रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि हम ऐसा हिंदू-मुसलमान करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। क्या वही राजनीति सामने आ रही है? बहरहाल पुलिस विशेषज्ञों का मानना है कि इलाके के ढाबों, होटलों और खोमचेवालों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल, पता आदि का संपूर्ण डाटा 'बीट कांस्टेबल' के पास होता है। तो फिर जांच के लिए छापामारी करने को हिंदू दबंगइयों को किसने निर्देश दिए थे? हरी झंडी दिखाई थी? यह हरकत आपराधिक और दंडनीय है, माना जाता है कि ये कथित हिंदू हुड़दंगी एक निश्चित राजनीतिक संरक्षण में पलते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे असामाजिक तत्त्वों को 'आस्तीन के सांप' करार दिया था। उप्र और उत्तराखंड में कांवड़-यात्राएं आयोजित की जाएंगी, जबकि कश्मीर में 'अमरनाथ यात्रा' शुरू हो चुकी है। उस यात्रा के दौरान प्रबंध करने वाले सभी मुसलमान होते हैं। वहां हिंदू-मुसलमान के बीच धार्मिक समभाव, सौहार्द क्यों है?

सीएम का ढाई-ढाई साल वाला फार्मूला, संसदीय मखौल

सरयूसुत मिश्रा

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है. यह कांग्रेसी हाईकमान के उस नाटक के कारण खड़ा हुआ है जिसमें दो नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को ढाई-ढाई साल के लिए बांट दिया गया था..!!

अब वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ढाई साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है. डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के समर्थक हाईकमान से अपना कमिटमेंट पूरा करने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस ने बीजेपी को एक्सपोज कर बेहतर गवर्नेंस के लिए सरकार बनाई थी लेकिन वहां ठीक उल्टा हो रहा है. अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि राज्य की सरकार का चलना भी बाधा दौड़ के साथ ही हो सकेगा.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं. ढाई-ढाई साल वाले फार्मूले पर जब उनसे पूछा गया, तब वह कहते हैं कि, यह मसला हाईकमान के ध्यान में है और इस पर वो ही निर्णय करेगा. इससे एक नया विवाद शुरू हो गया कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा दूसरा कौन हाई कमान है? इससे यह बात भी एक्सपोज हो गई कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार ने बनाया

गांधी परिवार में भी सोनिया गांधी उम्र के कारण अब लगभग पार्टी गतिविधियों से दूर हो गई हैं. अब तो कांग्रेस हाईकमान राहुल प्रियंका भाई-बहन ही बने हुए हैं. ढाई-ढाई साल का फार्मूला कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनाया. पहले जिसको ढाई साल का मौका मिला, उसने दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ी. फिर जो बगावत हुयी, उसके कारण पार्टी की सरकारों को चुनाव में पराजित होना पड़ा.

राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तथा टीएस सिंहदेव के बीच में भी ढाई ढाई साल वाला ही विवाद था, जिसका खामियाजा राज्य हितों को उठाना पड़ा. गांधी परिवार पार्टी की समस्याओं के समाधान के लिए किसी नीतिगत लाइन पर चलने की बजाय ऐसे समझौते करता है, जो ना संवैधानिक होते हैं और ना ही पार्टी के हित में.

मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के बीच में भी गांधी परिवार ने ऐसा समझौता कराया था कि,पार्टी अध्यक्ष का पद वह छोड़ देंगे और वह सिंधिया गुट को मिलेगा. यह कमिटमेंट भी जमीन पर नहीं उतर पाया और कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी.

कर्नाटक में भी ऐसा ही माहौल दिखाई पड़ रहा है. अब तो डी.के. शिवकुमार के समर्थक विधायक सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने लगे हैं कि, उनके नेता को यदि सीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा.

संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है. सीएम के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है. डिप्टी सीएम का ट्रेडीशन भाजपा द्वारा यह जातिगत समीकरण साधने की दृष्टि से की गई. बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया कि, किन्हीं भी दो नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल सीएम कुर्सी को बांटा हो. कांग्रेस ने तो जहां भी डिप्टी सीएम बनाया वहां ढाई-ढाई साल का फंडा है. पद के बंटवारे को ही निर्णय का आधार बनाया जो आगे चलकर फ्लॉप साबित हुआ.

ढाई-ढाई साल का मुख्यमंत्री पद बांटने का हाईकमान का निर्णय संसदीय व्यवस्था का मखौल है. मुख्यमंत्री का चयन विधायकों द्वारा किया जाता है. अगर विधायक दल ने नेता के चयन का मामला हाईकमान पर भी छोड़ा है, तो ढाई-ढाई साल की पद्धति संवैधानिक नहीं कहीं जा सकती. यह तो सौदेबाजी हुई. जहां सरकारों में सीएम पद ही सौदेबाजी से शुरू हुई है, वहां तो पूरी सरकार सौदेबाजी पर ही सिमट जाएगी.

एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वह फिर सरकारी सिस्टम को एटीएम के रूप में हाई कमान के लिए उपयोग करता है. जब एटीएम फुल होता है तो फिर अपने कमिटमेंट से हाईकमान पलट जाता है. उसका टारगेट पार्टी नहीं बल्कि पर्सनल गेन होता है.

राजनीतिक दलों में हाईकमान पद्धति एक सच्चाई बनी हुई है. बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी देश की सारी पार्टियाँ परिवारवादी पार्टियों के रूप में काम कर रही हैं. इसलिए उन दलों में परिवार ही हाईकमान के रूप में काम करता है.

बीजेपी और वामपंथी दलों में संसदीय बोर्ड को हाईकमान कहा जाता है लेकिन इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता कि सभी दलों में निर्णय कुछ खास स्तर पर लिए जाते हैं. अगर कोई राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता पर काबिज है, तो फिर तो प्रधानमंत्री ही मूल रूप से हाईकमान की भूमिका निभाता है.

जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वहां तो गांधी परिवार ही हाईकमान है. लोगों को भ्रम में डालने के लिए भले ही निर्वाचन की प्रक्रिया करके किसी को भी अध्यक्ष बना दिया जाए लेकिन निर्णय तो गांधी परिवार के हाथ में ही रहता है. वह भी आजकल भाई-बहन पर सिमट गया है.

कांग्रेस हाई कमान ने कर्नाटक में ढाई-ढाई साल का यदि असंसदीय कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए. वैसे भी कर्नाटक में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी उस समय पार्टी की कमान डी.के. शिवकुमार के हाथ में थी. कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि, इस फार्मूले की सौदेबाजी किस कीमत पर की गई है? इस सौदेबाजी को पूरा करने के लिए कर्नाटक करप्शन का शिकार हो गया है. जिस कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप पर अपना अभियान चलाया था, वह सरकार में आने के बाद खुद ही इतनी भ्रष्टाचार घिर गयी कि, भाजपा सरकार के एक भी आरोपों की ना तो जांच करा पाई ना ही किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी. ढाई-ढाई साल की सौदेबाजी अगर राहुल गांधी का संगठन सृजन का आधार है तो फिर कांग्रेस का विकार कोई भी दूर नहीं कर सकता. विकार को ही लाभ का प्रकार मानने वाली कांग्रेस की नीति पदों को बेचने खरीदने की नीति बन गई है. यह लोकतंत्र के लिए घातक है.

बेटियों के लिये मोह बढ़ना संतुलित समाज का आधार

अमिताभ पाण्डेय

दुनियाभर में माता-पिता आमतौर पर अब तक बेटियों की तुलना में बेटों को ज्यादा पसंद करते आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म, महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब लड़के की तुलना में लड़कियों को अधिक पसंद किया जाने लगा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह कम है और संभवतः लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह ज्यादा है। नए साक्ष्य एवं अध्ययन इस बदलाव का संकेत देते हैं, जो संभवतः बढ़ते एकल परिवार परम्परा, तथाकथित आधुनिक-सुविधावादी जीवनशैली एवं कैरियर से जुड़ी प्राथमिकताओं के चलते लड़कों से जुड़े एक सूक्ष्म भय, उपेक्षा एवं उदासीनता को उजागर करते हैं। 'द इकोनॉमिस्ट' द्वारा ताजा प्रकाशित रिपोर्टों में, लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में कुछ ऐसे ही दिलचस्प रुझान सामने आए हैं, जिसमें लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में माता-पिता अब लड़कों की तुलना में लड़कियों को भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक पसंद कर रहे हैं। विकासशील देशों में, लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह कम हो रहा है, जबकि अमीर देशों में लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक भूमिकाओं को लेकर विचारों में अंतर बढ़ता जा रहा है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान नीचे है, और इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 प्रतिशत है। वर्तमान प्रगति की दर से, पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, जो दर्शाता है कि प्रगति की समग्र दर धीमी है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि दुनिया भर में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत के लिये लैंगिक समानता की दिशा में दो पायदान की गिरावट का सबसे बड़ा कारण महिला समानता को लेकर चल रहे आन्दोलन है। भारत की बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक में बुलंदियां छू रही हैं। वे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में उल्लेखनीय भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है। सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धि योजना' जैसे सराहनीय पहल के जरिए बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी की चौखट पर खड़ी दुनिया में बड़े व्यापक बदलाव हो रहे हैं। इंसानी रिश्तों की अहमियत को लेकर भी नई सोच पनप रही है। अब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है? दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता, परिवार सार-संभालकर्ता, माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी निर्वाहकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने से अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिये अधिक संवेदनशील है। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं।

पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। भारत में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। जबकि सदियों से भारत की समाज-व्यवस्था एवं परिवार-परम्परा पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। जिसके चलते शिशु लिंग अनुपात में असंतुलन बढ़ता गया है। देश में हुई 2016 की जनगणना में लड़कों की तुलना में लड़कियों की घटती संख्या के आंकड़े चौंकाते ही नहीं बल्कि दुखी भी करते हैं। जिस तरह से लड़के-लड़कियों का अनुपात असंतुलित हो रहा है, उससे ऐसी चिन्ता भी जतायी जाने लगी है कि यही स्थिति बनी रही तो लड़कियां कहां से लाएंगे? हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में 2016 में प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले महज आठ सौ छह लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है।

जन्म से पहले ही पता चल जाए कि लड़की यानी बालिका पैदा होगी तो माता-पिता उसकी जान लेने से भी नहीं कतराते। कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं इसी सोच का परिणाम बनी। पिछली सदी में समाज के एक बड़े वर्ग में यह एक विभीषिका ही थी कि परिवार की धुरी होते हुए भी नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं था जिसकी वह अधिकारिणी थी। उसका मुख्य कारण था सदियों से चली आ रही कुरीतियाँ, अंधविश्वास व बालिका शिक्षा के प्रति संकीर्णता। कितनी विडम्बना है कि देश में हम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा बुलन्द करते हुए एक जोरदार मुहिम चला रहे हैं उस देश में लगातार बालिकाओं की संख्या घटने का दाग लगता रहा है। यह दाग 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प पर भी लगा है और यह दाग हमारे द्वारा नारी को पूजने की परम्परा पर भी लगा है। लेकिन प्रश्न है कि हम कब बेदाग होंगे? लेकिन अब इस संकीर्ण सोच में बदलाव आना एक सुखद संकेत है।

अच्छे भविष्य के लिए हम बेटियों की पढ़ाई से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे हमारे संकल्प को बताते हैं, हमारी सदिच्छा को दिखाते हैं, भविष्य को लेकर हमारी सोच को जाहिर करते हैं, लेकिन वर्तमान की हकीकत इससे उलट है, इसे बदलने में अभी भी लम्बा सफर तय करना होगा। बालिकाएं पढ़ाई में अपने झंडे भले ही गाड़ दें, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की क्रूरताएं कई तरह की हैं। शताब्दियों से हम साल में दो बार नवरात्र महोत्सव मनाते हुए कन्याओं को पूजते हैं। लेकिन विडम्बना देखिये कि सदियों की पूजा के बाद भी हमने कन्याओं को उनका उचित स्थान और सम्मान नहीं दे पाये हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को लिंग समानता के वैश्विक आंदोलन की किसी भी तरह अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 वैश्विक लैंगिक अंतर का आकलन और तुलना करने के लिए एक समझने योग्य ढांचा प्रदान करके और उन देशों को उजागर करके जो इन संसाधनों को महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप से विभाजित करने में रोल मॉडल हैं, रिपोर्ट अधिक जागरूकता के साथ-साथ नीति निर्माताओं के बीच अधिक आदान-प्रदान के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। तभी भारतीय समाज में लिंगभेद की मानसिकता खत्म होगी और लैंगिक

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस 11, प्रेस काम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भारती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक - स्मिता पटेल, स्थानीय संपादक —हाकम सिंह गुर्जर
प्रकाशन से संबंधित समस्त समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहियों के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय का रहेगा। रजि. नं. भोपाल डिवी. 48 म. प्र. ई-मेल : dspbpl67@gmail.com, वेबसाईटः dainiksandhyaprakash.in

जिला स्तरीय पूर्व सैनिक कल्याण बैठक संपन्न कार्यक्रम में कलेक्टर भी शामिल हुए

आष्टा। जिला कलेक्टर बाला गुरु की अध्यक्षता एवं भोपाल से पधारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजीव खत्री की विशिष्ट उपस्थिति में कलेक्टर सभागृह में पूर्व सैनिक वीर नारियों की बैठक संपन्न हुई । वीर नारियों,पूर्व सैनिकों की विभिन्न राजस्व, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, एवं प्रशासनिक क्षेत्र की समस्याओं के आवेदन स्वीकार किए गए और उन्हें कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया द्यएक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी म.प्र द्वारा दिवंगत सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का निवेदन किया जिस पर नियम अनुसार कार्रवाई करने का विश्वास व्यक्तकिया गयाद्यएक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष संतोष शर्मा के संयोजन में कलेक्टर महोदय एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय को पुष्प पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करते हुए सोसाइटी की म.प्र. सैनिक कल्याण पत्रिका भारतीय सैनिक एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया द्यबैठक के पश्चात शहीद सैनिकों की स्मृति में कलेक्टर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया द्यसैनिक कल्याण की बैठक में मुख्य रूप से वीरनारियां,पूर्व जिला कल्याण संयोजक सूबेदार कृष्ण मुरारी शर्मा, मोहन सिंह चंद्रद्य, सैनिक कल्याण कार्यालय प्रभारी महेश विश्वकर्मा, जिला सह प्रभारी मुकेश पेठद्यरिया, जिला संयोजक सूबेदार मेजर एच. एन. वर्मा, आष्टा से सूबेदार मोहर सिंह मेवाडा सूबेदार ज्ञान सिंह सोनाणिया, हवलदार राकेश कुमार मेवाड़ा, मुकेश इटावदिया पटवारी, कृष्णा मेवाड़ा, बलराम सिंह वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, एवं बुधनी,भेरूंडा ,इछावर जावर सहित पूरे जिले से 100 से अधिक पूर्व सैनिक एवं वीर नारी बैठक में उपस्थित रहे।

मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

छतरपुर। 6 जुलाई को मोहर्रम त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर बलबीर रमन, एसडीएम अखिल राठौर सहित अन्य अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर नागदेवे ने सभी से सौहार्दपूर्ण परम्परा के अनुरूप सद्भावना, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाने की अपील की। उन्होंने पर्व के दौरान साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, ट्रांसफॉर्मर सुधार, पेयजल, सडक से आवारा पशुओं को हटाने की कार्यवाही, सड़क मरम्मत तथा आवश्यक व्यवस्था के संबंध में सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जिसमें डॉक्टर की उपस्थिति रहे, पेयजल, प्रकाश सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम के अवसर पर निर्धारित रूट के अनुसार ही ताजिया का जुलूस निकाला जाए। और विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि ताजिया जुलूस के रास्ते में लटके हुए बिजली के तारों एवं केबलों को कसकर ऊंचा करें।

साथ ही बैठक में आयोजन समितियों से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा जिला होमगार्ड कमांडेंट को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों से सुझाव भी लिए गए।

सुल्तानपुर बिनेका रेंज के रेंजर टी आर कुलस्ते जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अधिकारी एवं कर्मचारी साथ में रेंजर प्रशांत खरे रघुराज मालवीय वन रक्षक राजू बरकरें शिक्षक एवं सुल्तानपुर के गढ़मान्य लोग।

सांसद एवं विधायक ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि वितरित

नीमच। देश एवं प्रदेश की भावी पीढ़ी, प्रतिभाएं भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 2047 तक वर्ल्ड लीडर बनेगा। देश का हर एक विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को हांसिल करें। यह बात नीमच, मंदसौर, जावरा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने शुक्रवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटाप की राशि वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कही। इस मौके पर विधायक श्री दिलीप सिह परिहार, न.पा.अध्यक्ष श्रीमती स्वाति चौपड़ा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओअमन वैष्णवभी मंचासीन थे। सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने अपने उदबोधन में विद्यार्थियों का आव्हान किया, कि वे जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे, उस क्षेत्र में जाने के लिए समर्पित होकर अपने लक्ष्य, मंजिल को हांसिल करने का प्रयास करें। उन्होने विद्यार्थियों से कहा, कि वे अच्छे वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, व्यापारी आदि बनकर, अपना परिवार, गांव, शहर, और जिले और प्रदेश का नाम रौशन करें। उन्होने कहा, कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 11 सालों में भारत काफी बदल गया है। सांसद ने विद्यार्थियों से कहा, कि यह समय उनके जीवन का टर्निंग पाईंट है। इस समय वे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे हांसिल करने का प्रयास करें। उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी।

विधायक नीमच श्री दिलीप सिह परिहार ने कहा, कि शिक्षा ऐसा धन है, जो कोई भी किसी से छिन नहीं सकता, विधा, धन बांटने से बढ़ता है। उन्होने कहा, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें, साईकिल, छात्रवृत्ति, लैपटाप, स्कूटी आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आज प्रदेश के 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि सिंगल क्लिक से प्रदान की जा रही है। विधायक ने कहा, कि उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में डोम निर्माण का कार्य भी शीघ्र करवाया जाएगा। जिससे विद्यार्थियों को सुविधा होगी। सांसद श्री गुप्ता, विधायक श्री परिहार एवं अतिथियों ने प्रतिक स्वरूप 10 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को लैपटाप की राशि के चैक भी प्रदान किए।प्रारंभ में अतिथियों ने मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.एम.मांगरिया एवं श्री मनोज जैन, श्री प्रलय उपाध्याय व शिक्षकगणों ने अतिथियों का स्वागत किया।इस अवसर पर भोपाल से मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। जिसे मंचासीन अतिथियों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने देखा व सुना। इस मौके पर एसडीएम श्री संजीव साहू, प्राचार्य श्री अनिल ठ?यास, श्री आदित्य मालू, श्री संतोष चौपड़ा, लोकेश चांगल सहित विद्यालय का स्टाफ, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

प्रतिभा शाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लैपटॉप राशि का वितरण

औबेदुल्लागंज (संवाददाता)-प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75त्न या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की।

औबेदुल्लागंज ब्लॉक में प्रोत्साहन देने के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम सांदीपनि विद्यालय औबेदुल्लागंज में आयोजित किया गया।

विधायक सुरेंद्र पटवा ने छात्र एवं छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रोत्साहित किया।ब्लॉक से आए सभी विद्यालय एवं पटवा ने साथ में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का सीधा प्रसारण टीवी पर देखा।सभी छात्रों ने अपने अनुभव साझा किया और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं शिक्षकों को दिया। एवं उन्हें भविष्य में क्या बना है यह भी बताया।

संदीपनी स्कूल विद्यालय की प्राचार्य चंद्रावती अतुलकर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी का आभार व्यक्त किया गया कार्यक्रम का संचालन सीमा सोनपुरे ,डॉक्टर दीप्ति माहेश्वरी,और आनंद तिवारी ने किया। वहीं कुमारी मोनिका शासकीय कन्या शाला मंडीदीप द्वारा जोरदार उद्बोधन किया गया और कुमारी अल्फिया एम एल बी कन्या शाला औबेदुल्लागंज द्वारा भी अपने सफलता के बारे में बताया गया। सांदीपनि विद्यालय के छात्र अजय उइके एवं छात्र अंशिका नामदेव द्वारा अपनी सफलता के बारे में बताया गया।

न्यायालय में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान 30 सितंबर तक चलेगा

छतरपुर। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा ए.डी.आर भवन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीशगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मेन मीडियेशन मॉनीटरिंग कमेटी, नई दिल्ली के तत्वावधान में 90 दिवसीय मीडियेशन फॉर दी नेशन (राष्ट्र के लिए मध्यस्थता) अभियान अंतर्गत जिला एवं समस्त तहसील न्यायालयों द्वारा मीडियेशन अभियान के दौरान मीडियेशन प्रकिया के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को रेफर किया जाकर अधिक से अधिक मामलों का निराकरण हेतु अभियान है जिसमें उक्त अभियान जुलाई माह से आरंभ होकर 30 सितम्बर तक चलाया जाएगा।

मीडियेशन राष्ट्रव्यापी अभियान में मीडियेशन योजना के माध्यम से वैवाहिक प्रकृति, मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चौक वाउन्स, वाणिज्यिक विवाद, सर्विस मेटर, कन्ज्यूमर विवाद, पार्टीसन, लेण्ड एक्यूजीशन, एविक्शन सूट, आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण अन्य सिविल प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले निराकृत किए जाएंगे। उक्त आशय का संदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समस्त तहसील न्यायालयों को व्ही.सी. के माध्यम से दिया साथ ही उक्त अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण एवं समस्त स्टेक होल्डर से अपील की। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश उपेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय आर.के. देवलिया, जिला न्यायाधीश कविता वर्मा, आशीष श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश, हिमांशु शर्मा, निवेश कुमार जायसवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती निवेश जायसवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विष्णु प्रसाद सोलंकी एवं अन्य न्यायिक अधिकारी रानो बघेल, प्रेरणा जैन, अरविंद सिंह गुर्जर, दिव्यांशु गुप्ता, राहुल जैन,आकांक्षा गर्ग, संघशिखा वंशकार, एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी वीरेन्द्र चढ़ार सहित अन्य न्यायालयीन स्टाफ मौजूद रहे।

हेमंत खंडेलवाल की चाहत गुटबाजी नहीं हो

इंदौर। बैतूल विधायक और संघ के करीबी हेमंत खंडेलवाल बीजेपी मप्र के नए प्रदेशाध्यक्ष हो गए हैं। पार्टी का झंडा अब उनके हाथ में है।

इंदौर से वैसे खंडेलवाल का बहुत ज्यादा राजनीतिक कनेक्शन नहीं रहा है। लेकिन, संघ की डोर के चलते कई नेता उनके साथ इसी के साथ जुड़े हुए हैं।

उनके प्रदेशाध्यक्ष बनते ही अगले दिन शहर के प्रमुख चौराहों पर एक पोस्टर राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा में भी रहा, जो खंडेलवाल को बधाई देने वाले थे। चर्चा अब इस पोस्टर के नेताओं की चलने लगी है क्या यह फिर पॉवर में आएंगे और क्या यह खंडेलवाल के करीबी नेता हैं।

पहले बताते हैं खंडेलवाल खुद क्या बोलेः खंडेलावल ने प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पहला भाषण देते हुए कहा कि- जो अच्छा काम करेगा, उसका सम्मान होगा और जो दाएं-बाएं करेगा उसे दिक्कत होगी। बीजेपी मेरे रग-रग में है। कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। यानी गुटबाजी के परे पार्टी में योग्य का सम्मान होगा।

इंदौर में लगे हैं ऐसे पोस्टरः इंदौर में प्रमुख तौर पर तीन तरह के पोस्टर लगे हैं। पहला पोस्टर सामान्य है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हेमंत खंडेलवाल, सीएम मोहन यादव की

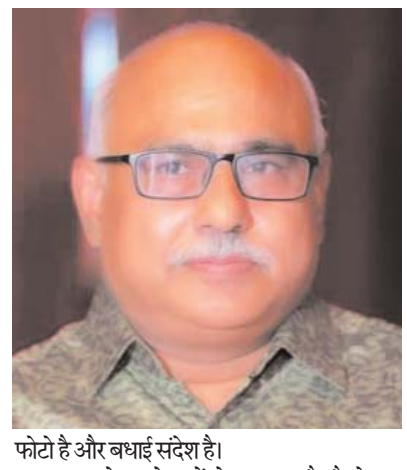

फोटो है और बधाई संदेश है।

दूसरा पोस्टर नेताओं से भरा हुआ है। है तो यह भी खंडेलवाल के लिए बधाई संदेश वाला है। इसमें पीएम, सीएम और खंडेवाल के साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक व मंत्री विश्वास सारंग, विधायक मनोज पटेल, विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ के साथ ही सावन सोनकर और पूर्व बीजेपी नगराध्यक्ष इंदौर गौरव रणदिवे की फोटो चस्पा हैं।

तीसरा पोस्टर भी लगा है जिसमें सीएम मोहन यादव और खंडेलवाल के साथ ही रणदिवे, प्रताप करोसिया, बीजेपी नगर मंत्री निक्की करोसिया, नागेश सिरसिया की फोटो चस्पा है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही होर्डिंग और पोस्टर में इंदौर शहर के दिग्गज नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला भी पोस्टर-होर्डिंग से नदारद हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा को भी पोस्टर में जगह नहीं दी गई है।

चावड़ा, रणदिवे, सोनकर सभी को बड़ी आस

मोहन यादव द्वारा सीएम पद संभालने के बाद सभी राजनीतिक आयोग, मंडल को भंग कर दिया गया और नियुक्तियां खत्म हो गई। अब ऐसे में सभी नेताओं को उम्मीद है कि मोहन और हेमंत की जोड़ी जल्द ही नए सिरे से मंडल, आयोग में नियुक्ति करेगी।वहीं इंदौर नगराध्यक्ष का कार्यकाल दमदारी से पूरा करने वाले रणदिवे भी नई भूमिका तलाश में हैं, तो वहीं मनोज पटेल को भी कुछ ना कुछ चाहिए। वह खाली विधायक भर हैं।

वहीं गौड़ परिवार कोशिश में हैं कि विधायक मालिनी गौड़ को विश्राम दिया जाए और विधानसभा का टिकट एकलव्य को मिले। सभी अपनी भूमिकाओं की तलाश में हैं और इसलिए सभी ने यह पोस्टर चस्पा करके राजनीतिक गलियारों में प्रदेशाध्यक्ष के करीबी होने का संदेश दिया है।

झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन की कार्यवाही से हड़कंप दो क्लीनिक सील क्लीनिकों को बंद कर भाग खड़े हुए डॉक्टर

सिरोंज। गुरुवार को डॉक्टर संतोष साहू द्वारा किए गए इलाज से मासूम देव कुशवाह की मौत हो गई थी, इसको लेकर लटेरी में काफी हंगामा हुआ था, डॉक्टर संतोष साहू के साथ भीड़ द्वारा मारपीट भी की गई थी इसी घटना से संज्ञान लेते हुए लटेरी स्वास्थ्य राजस्व और पुलिस प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ शख्त कदम उठाया गया है। संयुक्त टीम द्वारा लटेरी के झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिकों की जांच की गई, नगर में प्रशासन की कार्यवाही को देखकर लटेरी के झोलाछाप डॉक्टर अपनी अपनी क्लीनिकों को बंद कर भाग खड़े हुए। मलनिया रोड पर दो क्लीनिक और एक पैथोलॉजी सेंटर खुले पाए गए, प्रशासन द्वारा इनके संचालकों से वैध डॉक्यूमेंट मांगे गए, लेकिन ये डॉक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट टीम को नहीं बता पाए, तो प्रशासन ने दोनों क्लीनिक और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया।

स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्य प्रणाली से पनप रहे झोलाछाप डॉक्टरः झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रदेश सरकार के आदेश के

बाबजूद लटेरी बीएमओ सहित प्रशासन भी निष्क्रिय बना हुआ है। हमारे द्वारा कई बार खबरों के माध्यम से प्रशासन को आगाह भी किया है। लेकिन इनकी जांच की हिम्मत प्रशासन से लेकर बीएमओ तक नही जुटा पा रहे है। कोई ठोस कार्यवाही न किए जाने के कारण झोलछाप डॉक्टरों की तादाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती ही जा रही है वह लगातार मरीजों को मौत बांटने का काम कर रहे हैं। लटेरी प्रशासन सहित बीएमओ भी इसमें साझेदार बने हुए है। नगर लटेरी सहित ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है दिनों दिन इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, इनके पास न तो कोई डिग्री है न अनुभव और न ही लाइसेंस। इसके बाबजूद वह बेरोक टोक धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों को लटेरी बीएमओ का कोई डर नहीं है। शहर एवं ग्रामीण इलाकों को मिलाकर इनकी संख्या सैकड़ा को पार कर चुकी है। इनके द्वारा दी जाने वाली अनाप-शनाप दवाइयां कई मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। अगर यह कहा जाए कि झोलाछाप डॉक्टर दवा नहीं बल्कि मौत बांट रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए।

इनका कहना है

आज प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा नगर के क्लीनिकों की जांच की गई, अधिकतर क्लीनिक बंद पाए गए, मलनियां रोड पर दो क्लीनिक खुले पाए गए, उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए उनको सील किया गया है।

अभिषेक उपाध्याय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी लटेरी

रेनो इंडिया के नए आर स्टोर ने मध्य प्रदेश में किया प्रवेश, इंदौर और सागर में खोले नए स्टोर

सागर। रेनो रीथिंक ब्रांण्ड ट्रांसफोर्मेशन स्ट्रैटेजी के तहत अपनी बोल्ड यात्रा को जारी रखते हुए फ्रांस के कारनिर्माता रेनो ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व की सब्सिडरी रेनो इंडिया ने इंदौर एवं सागर में दो नए आर स्टोर खोलने की घोषणा की है। इस लॉन्च के साथ ब्राण्ड ने मध्य प्रदेश में अपनी नई रीटेल पहचान की शुरूआत की है। उपभोक्ताओं की बदलती उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए रेनो इंडिया की ब्राण्ड एक्सपीरिएंस एवं ट्रांसफोर्मेशन स्ट्रैटेजी के तहत डिज़ाइन इनोवेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन एवं उपभोक्ता-उन्मुख सर्विस के संयोजन के साथ यह रोलआउट किया गया है।इस अवसर पर श्री फ्रांसिस्को हिडाल्गो, वाईस प्रेज़ीडेन्ट, सेल्स एण्ड मार्केटिंग- रेनो इंडिया प्रा. लिमिटेड ने कहा, ''मध्य प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण मार्केट है, राज्य में हमारे वाहनों को खूब पसंद किया जा रहा है। ऐसे में इंदौर और सागर में नए आर स्टोर्स की ओपनिंग रेनो. रीथिंक. स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारे कारोबार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह स्ट्रैटेजी उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए रेनो ग्लोबल ब्राण्ड के मूल्यों के अनुरूप उन्हें सकारात्मक अनुभव प्रदान करने पर फोकस करती है। मध्य प्रदेश अब हमारे नए आर स्टोर मैप पर आ गया है, ऐसे में हम देश भर में भविष्य के अनुकूल रीटेल सिस्टम बनाने की दिशा में और आगे बढ़ गए हैं। अपने विस्तार को जारी रखते हुए हम उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने तथा ऑटोमोटिव रीटेल में नए बेंचमार्क स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। जल्द ही हमने भारत में 2 और नए आर स्टोर खोलने की योजना बनाई है।

ओबीसी को आरक्षण देने का कानून है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह छिपाया गया: विभा पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की नीयत नहीं रखती है। उसकी कलई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुल गई। इसका उदाहरण यह है कि मप्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध दर्ज किया तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए राज्य की मोहन यादव सरकार से जवाब मांगा है।

विभा पटेल समेत अपॉक्स के संरक्षक भुवनेश पटेल, ओबीसी महासभा के धर्मेंद्र कुशवाह, पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के जीपी माली, मध्य प्रदेश ओबीसी, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिवक्ता संघ के तुलसी राम वर्मा आदि ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का विधानसभा से कानून पारित है। कानून पारित होने के बाद यह राज्य सरकार की बाध्यता में शामिल है। इस तथ्य से भाजपा सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं करा रही है।मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 4 (2) के तहत सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सार्वजनिक तौर पर कहती है कि हम 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब बात कोर्ट में आती है तो ये अपने ही कानून का विरोध कर रही हैं।

नेताओं का कहना है कि पिछड़ा वर्ग को 27त्न आरक्षण देने के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार का दुलमुल रवैया है। यह आरक्षण कमलनाथ सरकार के समय कानून बनाकर ओबीसी को दिया गया था। आरक्षण लागू न हो, इसके लिए आरएसएस और भाजपा ने पूरे प्रयास किए। मामले को सब-ज्यूडिस बताकर भ्रांति फैलाने का काम किया। लेकिन शुक्रवार की सुनवाई से यह फिर से स्पष्ट हो गया है कि ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। यह लागू है।

नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दोमुंही रवैये के कारण यह मामला उलझा। ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने के लिए भाजपा की शुरू से ही रणनीति रही है।

भाजपा जानबूझकर अदालत में लचार दलील देकर आरक्षण को समाप्त होने का रास्ता खोलती रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा के दोहरे चरित्र को भलीभांति समझ रहा है। इसका उदाहरण यह है कि राज्य की भाजपा सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के विषय में अपनी सहमति का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया और न ही वैज्ञानिक, वैधानिक, व्यवहारिक तथ्यों के साथ मप्र का पक्ष रखा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने संबंधी तुरंत कोई आदेश देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने मामले को उलझाया। इस कारण कई शिक्षित और उच्च शिक्षित युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित होकर अब ओवरएज हो गए हैं।

इंदौर नगर निगम में 150 करोड़ का बिल घोटाला

ईडी ने अभय राठौर और आरोपियों की 34 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने नगर निगम इंदौर के 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में संपत्तियां अटैच करने का काम तेज कर दिया है। द सूत्र ने सात जनवरी को ही इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी कि ईडी ने मुख्य आरोपी निगम इंजीनियर अभय राठौर के साथ ही अन्य आरोपियों और ठेकेदारों की संपत्तियों की लिस्ट बना ली है और जल्द अटैच किया जाएगा।

34 करोड़ की प्रापर्टी की अटैच

ईडी ने निगम के इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की 34 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित 43 अचल संपत्तियां (आवासीय और कृषि दोनों) शामिल हैं। ईडी ने फर्जी बिल घोटाले के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है।

ईडी की जांच से पता चला है कि नगर निगम इंदौर के अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न ठेकेदारों ने आपराधिक साजिश रची और जमीनी स्तर पर कोई काम किए बिना ÷ड्रेनेज निर्माण कार्य÷ के फर्जी बिल पेश करके अपराध से आय अर्जित की। आरोपी ठेकेदारों को अवैध रूप से 92 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ईडी की जांच से पता चला है कि ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम पर बनाए गए म्यूल खातों का उपयोग करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और उक्त नकदी को आरोपी ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच बांट लिया गया।

इससे पहले ईडी ने 5 व 6 अगस्त 2024 में इंदौर में आरोपियों के 20 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ 22 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। अभी आगे की जांच जारी है।

घोटाले के मुख्य आरोपी नगर निगम के इंजीनियर अभय सिंह राठौर मुख्य निशाने पर है। उसके खुद के नाम की संपत्ति के साथ ही बहन मीरा राठौर, पिता प्रकाश सिंह राठौर और मां सरला के नाम की प्रापर्टी अटैच हो रही है। वहीं मोहम्मद एहतेश्याम खान उर्फ काकू, मोहम्मद असलम खान, रहेल खान व बिल्किस खान की भी संपत्तियां है। साथ ही राहुल बढेरा, रेणु बढेरा. मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद साजिद, मीरा शर्मा, राजेंद्र शर्मा, किरन सिरोजिया, राजकुमार साल्वी, शीला बढेरा की भी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। ईडी ने नगर निगम घोटाले में मारे गए छाप के बाद औपचारिक तौर पर बताया था कि इंदौर सब रीजनल कार्यालय ने मनी लाण्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत निगम के फर्जी बिल घोटाले में 5 और 6 अगस्त को इंदौर में 20 ठिकानों पर छापे मारकर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 1.25 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई और बैंक खाते, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड और इक्विटी के रूप में कुल 20.8 करोड़ रुपए के निवेश को फ्रीज कर दिया गया। आगे की जांच जारी है।

ईडी ने बताया कि आईएमसी फर्जी बिल घोटाले के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी की जांच से पता चला कि आईएमसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके विभिन्न ठेकेदारों ने आपराधिक साजिश रची और ड्रेनेज के निर्माण कार्य के फर्जी बिल पेश करके क्राइम किया और इससे कमाई की। जिस काम के लिए फर्जी बिल बनाए गए थे, उसका भुगतान करने से पहले न तो जमीन पर काम किया गया था और न ही आईएमसी के लेखा और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उसका सत्यापन किया गया था।

विभिन्न सेवाओं और बैचों के 8 अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों के लिए इंपैनल्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने विभिन्न सेवाओं और बैचों के 8 अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों के लिए इंपैनल्ड किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न सेवाओं और बैचों के आठ अधिकारियों के पैनल को मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों में भारतीय वन सेवा कमलजीत सिंह (IFoS:2004: BH) धीरज पांडे (आईएफओएस-2004 यूडी)- भारतीय डाक सेवा में जगदीप गुप्ता (आईपीओएस-2004), सुनील शर्मा (आईपीओएस 2004)। भारतीय सांख्यिकी सेवा में समरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव (आईएसएस 2004), सिलजो वीके (आईएसएस 2004), हेमा जायसवाल (आईएसएस 2004) और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में राजेंद्र कुमार अग्रवाल (आईआरपीएस 2000)शामिल है।

विनीत छतरी और दिव्यज्योति पटनायक चुने गए माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

गुड़गांव , एजेंसी। एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, एसएफबी और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं के लिए अग्रणी उद्योग संघ और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन (एसआरओ), माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) ने 4 जुलाई 2025 को गुड़गांव में आयोजित अपनी 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में एमएफआईएन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री विनीत छतरी और उपाध्यक्ष के रूप में दिव्यज्योति पटनायक की नियुक्ति की घोषणा की। नए अध्यक्ष श्री विनीत छतरी फिलहाल स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जबकि श्री दिव्यज्योति पटनायक अन्नपूर्णा माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं।एमएफआईएन बोर्ड और सदस्यों ने एमएफआईएन गवर्निंग बोर्ड में तीन नए सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें श्री भास्कर बाबू रामचंद्रन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, श्री कृष्णदास बी नायर, ईवीपी और कारोबारी प्रमुख - माइक्रोफाइनेंस, एक्सिस बैंक लिमिटेड और श्री ज्ञान मोहन, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं और ये छोटे एनबीएफसी-एमएफआई प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। निदेशक मंडल ने दो नए स्वतंत्र निदेशकों - सुश्री वीणा मनकर, संस्थापक और निदेशक, स्वाधार फिनएक्सेस और श्री सौरभ सिन्हा, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का भी स्वागत किया।

एचएंडएच एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के राजकोट में भारत के सबसे बडे सोलर पैनल फ्रेम प्लांट का उदघाटन किया

अहमदाबाद , एजेंसी। गुजरात स्थित एचएंडएच एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड ने राजकोट में भारत का सबसे बडा और सबसे उन्नत एल्युमीनियम सोलर फ्रेम मैन्युफेक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। राजकोट के चिभडा गांव में 24,000 मेट्रिक टन (एमटी) प्रति वर्ष क्षमता वाला यह प्लांट भारत में 6 गीगावाट तक के सौर संयंत्रों को सपोर्ट कर सकता है। इस प्लांट का उद्घाटन 4 जुलाई, 2025 को भारत सरकार के माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, एचएंडएच एल्युमीनियम की लीडरशिप टीम और सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। कंपनी ने 28,000 वर्ग मीटर के अत्याधुनिक और सोलर पैनल एल्युमीनियम फ्रेम के लिए आधुनिक और सबसे उन्नत प्लांट में लगभग रु. 150 करोड का निवेश किया है। प्लांट में ट्रायल प्रॉडक्शन जून 2025 के महीने में शुरू हो गया था और एक महीने के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। पूरी क्षमता पर प्लांट प्रति वर्ष रु. 700-750 करोड की बिक्री दर्ज करने में सक्षम होगा। यह प्लांट 300 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

पहली तिमाही में थमी रहेगी महंगाई, आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप ही रहने की उम्मीद

मुंबई, एजेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में महंगाई आरबीआई के अनरूप रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने पहली तिमाही के लिए सीपीआई 2.9त्न रहने की संभावना जताई है। यह स्थिति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की उम्मीद है। यह स्थिति अनुकूल सांख्यिकीय आधार और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से बनी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) का अनुमान 3.7 प्रतिशत लगाया है। पहली तिमही के लिए 2.9त्न, दूसरी तिमाही में 3.4त्न, तीसरी तिमाही में 3.9त्न और चौथी तिमाही में 4.4त्न रहने की संभावना जताई गई है। जून 2025 में बीओबी आवश्यक वस्तु सूचकांक (बीओबी ईसीआई) में वार्षिक आधार पर 1.8त्न की गिरावट दर्ज की गई, जो मई 2025 के 0.6त्न से अधिक है। यह लगातार तीसरा महीना है, जब सूचकांक नकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है। यह मुख्य रूप से सब्जियों और दालों की कीमतों में तेज सुधार, बेहतर उत्पादन और अनुकूल आपूर्ति स्थितियों के कारण हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया कि जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 2.6त्न पर स्थिर रहने की संभावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में आरबीआई के पास विकासोन्मुखी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ गुंजाइश होगी।

टॉप श्रेणी की सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट

टमाटर, प्याज, आलू (टॉप) श्रेणी की सब्जियों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जून में प्याज की खुदरा कीमतों में सालाना 26.1त्न और आलू में 20.3त्न की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। वहीं टमाटर 24त्न सस्ता हुआ। दालों में अरहर दाल में सबसे अधिक 23.8त्न की गिरावट देखी गई। यह लगातार चौथा महीना है जब इसमें दो अंकों की गिरावट रही। उड़द, मसूर और मूंग की कीमतें भी लगातार घट रही हैं, जिसे खरीफ फसलों की बेहतर बुवाई का समर्थन मिला।

अनाज, खास तौर पर चावल की खुदरा कीमतों में भी नरमी देखी गई, जहां जून में 5.1त्न की गिरावट आई। वहीं नमक और गुड़ जैसी वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। खाद्य तेलों की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुकूल रुझान से इसमें भी राहत मिल रही है।

मौसम का पड़ रहा असर

हालांकि, जून में मासिक आधार पर बीओबी सूचकांक में 0.6त्न की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन मौसमी रूप से समायोजित आंकड़े 0.7त्न की गिरावट दर्शाते हैं, जिससे पता चलता है कि यह वृद्धि मौसमी प्रभाव की वजह से थी। टमाटर की कीमतें मई की तुलना में जून में 36.1त्न बढ़ गईं, जो अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है। यह मानसून के शुरुआती प्रभाव और सामान्य मौसमी मूल्य परिवर्तनों का परिणाम है। हालांकि प्याज की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। यह जून में सिर्फ 0.4त्न घटी, जबकि मई में 9.8त्न की गिरावट थी।

आपूर्ति मजबूत करने की जरूरत

रिपोर्ट ने चेतावनि दी गई कि जून और जुलाई आमतौर पर टॉप कीमतों में मौसमी उलटफेर होता है, जिसमें कीमतों में ऊपर की ओर सुधार की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय सब्जी उत्पादन केंद्रों के विकास की सिफारिश की गई है।

भोपाल दुग्ध संघ में एनडीईआरपी का शुभारंभ

भोपाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, द्वारा भोपाल दुग्ध संघ (बीडीएस) में एनडीईआरपी (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी ईआरपी) का शुभारंभ किया गया। यह पहल न केवल भोपाल दुग्ध संघ के संचालन को और अधिक कुशल बनाएगी, बल्कि पूरे राज्य में डेयरी क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के कार्यकारी निदेशक श्री एस.रघुपति, एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) के प्रबंध निदेशक डॉ संजय गोवाणी तथा भोपाल दुग्ध संघ (बीडीएस) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रीतेश जोशी उपस्थित रहे।मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ प्रीतेश जोशी ने बताया कि इस अत्याधुनिक ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन मात्र एक माह की रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण किया गया, जो कि यह दक्षता, समर्पण और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है।

ईआरपी कार्यान्वयन से होने वाले प्रमुख लाभ

-रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि।
-खरीद, उत्पादन, वितरण और लेखा जैसे विभागों का एकीकृत प्रबंधन।
-संचालन में पारदर्शिता और समय की बचत।
-उत्पादकता और जवाबदेही में सुधार।
-डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की ओर एक और ठोस कदम।

घर से बिजनेस कर रहे हैं तो बदल ले बिजली कनेक्शन, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी घरों से व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई करेगी। यदि आपके घर में बिजनेस चल रहा है और बिजली का घरेलू कनेक्शन है, तो जुर्माना लग सकता है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से व्यवसाय के लिए गैर-घरेलू कनेक्शन लेने की अपील की है। भोपाल में बहुत से लोग घरों से बड़े-बड़े व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन उनके पास घरेलू कनेक्शन है। इससे न सिर्फ कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि बिजली की खपत भी अधिक हो रही है। ऐसे में कंपनी ने इस पर कड़ी नजर रखने के लिए अभियान शुरू किया है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जो भी उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल व्यवसायिक कार्यों के लिए कर रहे हैं, वे जल्द ही जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें। साथ ही, दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जो उपभोक्ता व्यवसाय के लिए गैर-घरेलू कनेक्शन लेंगे, वे इस समस्या से बच सकते हैं।भोपाल के कई क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन पर रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, प्राइवेट होस्टल, कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय चलाए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा कई बार ऐसे उपभोक्ताओं को गैर-घरेलू कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है। इसके बावजूद बहुत से लोग घरेलू कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि जिन उपभोक्ताओं ने जिस उद्देश्य के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार बिजली का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने घरेलू कनेक्शन लिया है तो वे केवल निवास के उद्देश्य से ही उसका उपयोग करें, ना कि व्यवसाय के लिए। व्यवसायिक उपयोग के लिए गैर-घरेलू कनेक्शन लिया जाना चाहिए।

आंकड़े : 94 करोड़ लोगों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा योजना लाभ

अंत्योदय-समावेशी विकास नीति से सशक्त हो रहा देश

नई दिल्ली, एजेंसी। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। 2015 में जहां भारत की महज 19 फीसदी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माना जाता था, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 64.3त्न तक पहुंच चुका है। यानी, 94 करोड़ भारतीय अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीते एक दशक में जो बदलाव आया है उसे अब लगातार अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। 2015 में जहां भारत की महज 19 फीसदी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माना जाता था, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 64.3त्न तक पहुंच चुका है। यानी, 94 करोड़ भारतीय अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी एकउल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सिर्फ संख्या की वृद्धि नहीं है बल्कि नीतियों के दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव भी दर्शाता है। पहले जहां यह कल्याण योजनाएं केवल दिखावटी या चुनावी भाषणों तक सीमित थीं वहीं अब उन्हें डेटा आधारित, कानूनी रूप से समर्थित और संस्थागत रूप से प्रमाणित ढांचे में समाहित किया गया है। इस बदलाव से गांव-गरीब का भी 'सिस्टम' के प्रति भरोसा जाग रहा है।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संकल्पना पर आधारित योजनाओं से बीते 10 वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि कल्याण सिर्फ अब सरकारी जुमला नहीं है बल्कि शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उसने कल्याणकारी योजनाओं को 'डिजिटल ट्रांसफर आधारित न्याय' में बदला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए।

अगर सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए तो आयुष्मान भारत-पीएमजय का नाम सबसे पहले आता है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। अब तक 6 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती मुफ्त इलाज और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा यह साबित करता है कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य को आम नागरिक का अधिकार बना दिया है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020 भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, अटल पेंशन योजना, किसान मानधन योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाएं वृद्ध नागरिकों को आर्थिक संबल दे रही हैं। आईएलओ का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न होकर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होनी चाहिए। यह दर्शन मोदी सरकार की योजनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

मेट्रो इन दिनों

इस फिल्म का सूत्र वाक्य है फॉलिंग आउट ऑफ लव इज़ नॉर्मल ! लेकिन इसमें प्रेम कहानियां हैं। मेट्रो के उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि सभी जोड़ियां टॉक्सिक प्यार के लफड़े में हैं। न उम्र की सीमा, न धर्म का बंधन ! प्यार मैन कोर्स जैसा और बाकी सब डेज़र्ट ! बुढ़ापा बेसहारा होता है और जवानी अकेली ! हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है प्यार, शादी, बच्चे और रिप्रोडक्शन ! सबको खुश रहने का हक है और इसके लिए सब कुछ जायज है, अगर किसी को कष्ट नहीं हो तो ! जहां किसी का किसी पर हक नहीं होता, वहां मोहब्बत होती है शक नहीं होता ! फिल्म में और एक और सूत्र वाक्य है शादी कुछ सिखाये या न सिखाये, एक्टिंग जरूर सिखा देती है !

मेरी बात लगी न कॉम्प्लिकेटेड! फिल्म ऐसी ही है ! इमोशनल, रिलेशनशिप बेस्ड म्यूजिकल ड्रामा ! चार जोड़ियां हैं। सबकी सेम प्रॉब्लम !फॉलिंग आउट ऑफ़ लव ! आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान एक युवा जोड़े की कहानी, जो आधुनिक रिश्तों में सोशल मीडिया और कमिटमेंट की जटिलताओं से जूझ रहा है। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा एक मिडिल-एज शादीशुदा जोड़ा, जिनके रिश्ते में बोरियत और बेवफाई की समस्याएं उभरती हैं। अली फजल और फातिमा सना शेख लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में फंसे एक जोड़े की कहानी, जहां करियर, प्यार और बच्चे के बीच संतुलन की जंग है। अनुपम खेर और नीना गुप्ता-बुजुर्ग जोड़े की कहानी, जो यह दर्शाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर प्रेम संभव है। ये सभी लोग मेट्रो शहरों के शानदार घरों में रहते हैं, बढ़िया खाते-पहनते हैं। आम आदमी जैसी कोई चिरकुट समस्या उनको नहीं है।

इतने पात्र हैं तो इतनी कहानियां भी हैं। इन सभी चरित्रों को इंट्रोड्यूज़ कराने में ही काफी वक्त निकल जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म धीमी लगती है, मगर फिर क्लाइमेक्स राहत देता है। फिल्म में गानों की भरमार है। हॉलीवुड म्यूजिकल की तरह प्रीतम, पापोन और चैतन्य राघव के गीत-संगीत को सूत्रधार के रूप में इस्तेमाल किया है, तो ये ही फिल्म में छाए रहते हैं। हर कहीं, हर कभी गाना शुरू हो जाता है, जो थका देता है।

फिल्म रिश्तों की सच्चाई या झूठाई, मेट्रो लाइफ की तन्हाई और जज्बातों को सादगी और भावुकता के साथ बयान करती है। यह अलग-अलग उम्र के लोगों के रिश्तों की जटिलताओं को दिखाती है. अनुराग बसु ने अपनी खास शैली में रिश्तों की जटिलताओं को सादगी के साथ पेश किया है। उनकी कहानी कहने की कला किरदारों को मानवीय और रिलेटेबल बनाती है। अगर आपको शहरी जीवन और रिश्तो की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आएगी लेकिन एक्शन पसंद करने वालों को यह फिल्म धीमी लगेगी। फिल्म में परदे पर इरफ़ान खान और केके मेनन को भी याद किया गया। अगर इरफ़ान होते तो मोंटी का रोल उनका होता, जिसे पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। केवल कोंकणा सेन हैं, जो 2007 में बनी इसकी पहली सीक्वल लाइफ इन मेट्रो में थी। फिल्म लम्बी है, करीब पौने तीन घंटे की, फिर भी कुछ किरदार अधूरे लगते हैं।

देखनीय लेकिन कुछ शर्तों और नियमों के साथ !

डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी

प्राडा-कोल्हापुरी चप्पल विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, कारीगरों ने की मुआवजे की मांग

मुंबई, एजेंसी। इटली की मशहूर लक्जरी फैशन ब्रांड प्राडा पर भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल की नकल कर भारी मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें प्राडा पर कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन का अनधिकृत उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि प्राडा को भारतीय कारीगरों को मुआवजा देना चाहिए और कोल्हापुरी चप्पल के व्यावसायीकरण पर रोक लगाई जाए।

मामला तब चर्चा में आया जब प्राडा ने अपने 'स्प्रिंग/समर 2026' फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पल जैसे डिजाइन की सैंडल पेश कीं, जिनकी कीमत 1 से 1.25 लाख रुपये

रखी गई। याचिका में दावा किया गया कि ये डिजाइन कोल्हापुरी चप्पल से हूबहू मिलते हैं, जो भौगोलिक संकेतक के तहत संरक्षित हैं। याचिका में प्राडा से सार्वजनिक माफी और कारीगरों को उनके शिल्प का श्रेय देने की मांग की गई है। साथ ही, कोर्ट से कारीगरों के लिए मुआवजे और त्वढ्ढ उल्लंघन की जांच का अनुरोध किया गया है। प्राडा ने स्वीकार किया कि उनके डिजाइन भारतीय हस्तशिल्प से प्रेरित हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक माफी या मुआवजा नहीं दिया गया। कंपनी का कहना है कि प्रदर्शित सैंडल डिजाइन चरण में हैं और व्यावसायीकरण की पुष्टि नहीं हुई है। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर में हस्तनिर्मित होती हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी से चली आ रही यह कला स्थानीय मोची समुदाय द्वारा वनस्पति-टैन्ड चमड़े से बनाई जाती है। याचिका में को-ब्रांडिंग और रेवेन्यू साझेदारी जैसे कदमों की मांग की गई है ताकि कारीगरों को उनके हुनर का उचित लाभ और पहचान मिले।

टाटा स्टील को 1,902 करोड़ रुपये का नोटिस; छह देशों से पॉलीथीन के आयात मामले में डंपिंग-रोधी जांच

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा स्टील को ओडिशा में अपने सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिज भेजने में कथित कमी के लिए जाजपुर में खान उप निदेशक से 1,902 करोड़ का मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया, उसे खान विकास और उत्पादन समझौते के संदर्भ में चौथे वर्ष के लिए खनिजों को भेजने में कमी के को लेकर एक मांग पत्र मिला है। वह इस नोटिस को उपयुक्त कानूनी मंच पर चुनौती देगी।

केंद्र सरकार ने भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन संघ की शिकायत के बाद छह देशों कुवैत, ओमान, कतर, मलयेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से पॉलीथीन के आयात की डंपिंग-रोधी जांच शुरू की है। आवेदक ने आरोप लगाया कि लीनियर डेंसिटी पॉलीएथिलीन की डंपिंग के बाद किए गए आयात से घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिससे पैकेजिंग फिल्म, तार और केबल जैसे विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की अधिसूचना के अनुसार, आवेदक ने डंप आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सबूत दिए?हैं।?अगर डंपिंग से घरेलू कंपनियों को भौतिक क्षति हुई है, तो डीजीटीआर आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।

मूंग-उड़द उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख कल, 7 जुलाई से खरीदी

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। जिन किसानों ने अबतक पंजीयन नहीं करवाया है वे फटाफट करवा लें। मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार तथा उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन हो चुका है।7 जुलाई से 6 अगस्त तक उपार्जन किया जाएगा। इस बार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रूपये प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7400 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। ध्यान रहे मूंग एवं उड़द के लिये संबंधित किसानों को पंजीयन के लिये किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, आईएफसी कोड सहित भूअधिकार ऋण पुस्तिका की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी।

बता दे कि प्रदेश के 36 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक मूंग फसल कटाई और प्रदेश के 13 जिलों में मई माह के तृतीय सप्ताह से जून माह के प्रथम सप्ताह तक उड़द फसल की कटाई की जाती है। प्रदेश में मूंग का संभावित क्षेत्राच्छादन 14.35 लाख हेक्टेयर, संभावित उत्पादन 20.23 लाख मीट्रिक टन है। इसी प्रकार उड़द का संभावित क्षेत्राच्छादन 0.95 लाख हेक्टेयर, संभावित उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

उपार्जित की जाने वाली मूग एव उड़द के लिये संबंधित किसानों को पंजीयन के लिये किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, आईएफसी कोड सहित भूअधिकार ऋण पुस्तिका की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा का होना अनिवार्य है। सिकमी/बटाई काश्तकार को पंजीयन के लिये आवेदन के साथ सिकमी के अनुबंध की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगी। भुगतान के लिये कम्प्यूटराईज प्रिंटेड रसीद उपार्जन करने वाली संस्था द्वारा प्रदाय की जायेगी जिसमें किसान का नाम, बैंक खाता क्रमांक तथा भुगतान योग्य राशि का विवरण होगा।इस रसीद पर उपार्जन केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर भी किये जायेंगे।

ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द के उपार्जन करने की जिम्मेदारी संबंधित उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं की होगी।उपार्जन केन्द्र से गोदाम तक मूंग-उड़द परिवहन करने के लिये परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति एवं अनुबंध की कार्रवाई की जायेगी। उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन उपार्जन मात्रा की समीक्षा भी होगी।

इन जिलों में होगी खरीदी

मूंग: नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट, सतना।

उड़द: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी, बालाघाट।

मूंग उड़द खरीदी के लिए किसानों को ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा।

राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में शामिल हुए महापौर विक्रम अहके

छिंदवाड़ा। लोकसभा सचिवालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा शासन के सहयोग से हरियाणा के गुरुग्राम मानेसर 3 एवं 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश भर से स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं सांसद विधायकों को आमंत्रित किया गया। नगर पालिक निगम महापौर विक्रम अहके भी इस सम्मलेन में अपनी सहभागिता दी। महापौर ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों से छिंदवाड़ा शहर के विकास एवं नवाचारों की चर्चा करते हुए विचारों को साझा किया।

तुलसी अमृत काटवले को कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोनीत

पांढुर्ना। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार पांढुर्ना जिला कांग्रेस में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। पांढुर्ना जिला प्रभारी गंगाप्रसाद तिवारी व कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश झलके व वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत विधि के जानकार तुलसी अमृत काटवले को पांढुर्ना जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तूफान के साथ भारी वर्षा होने की संभावना

छिंदवाड़ा। भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 120 घंटो के दौरान 5 जुलाई 9 जुलाई घने बादल रहने एवं बिजली, तूफान के साथ बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है । अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री. सेन्टीग्रेट के मध्य रहने की संभावना है । अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता 86-91 प्रतिशत एवं न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता 63-71 प्रतिशत रहने की संभावना है । आने वाले दिनों में हवा पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशाओ में बहने एवं 16-18 कि. मी. प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है ।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर की सख्त कार्रवाई

15 दिन में काटे 2257 चालान, 10.38 लाख की वसूली

छिंदवाड़ा। पुलिस द्वारा कल्याण चक्रवर्ती पुलिस उप महानिरीक्षक, छिंदवाड़ा रेंज के निर्देशन में रेंज स्तर पर चलाए गए विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के नेतृत्व में जिले भर में सघन वाहन चेकिंग एवं चालानी कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों पर कठोर कार्रवाई कर दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा।अभियान अवधि 16 जून से 3 जुलाई के दौरान जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर करवाई की गई जिसमें गलत साइड से वाहन चलाना151 रू. 75,500,यातायात नियमों का उल्लंघन करना2048 रू. 8,42,500,वाहन पत्रक व अन्य दस्तावेजों का अभाव58रू. 1,20,000 कुल 2257 रू. 10,38,000 शामिल हैं यह अभियान जिलेभर में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित यात्रा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने हेतु चलाया गया था। छिंदवाड़ा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर को प्राथमिकता दें। यह अभियान अभी भी जारी है।

शासकीय स्कूलों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है: कमेलश शाह

2932 विद्यार्थियों को मिली लैपटॉप की राशि

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के मेघावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल कैलाश नगर में आयोजित कार्यक्रम में अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जिले भर के 2932 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि वितरित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आठ विद्यार्थियों को 25-25 हजार रूपए के 2932 छात्रों को यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। कलेक्टर ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना न केवल विद्यार्थियों को डिजिटल युग से जोड़ने की दिशा में अहम हैं बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाइ के लिए भी प्रेरित करती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपर कलेक्टर अग्रिम कुमार, भाजपा के जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, भाजपा नेता विजय पांडे, सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।

विधायक बोले-आज शिक्षा की बुनियाद मजबूत हो रही

मुख्य अतिथि विधायक कमलेश प्रताप शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सार्थक प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों की स्थिति में पहले की तुलना में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले का इस वर्ष का परिणाम उल्लेखनीय रहा है, जो शासन की योजनाओं, शिक्षकों के समर्पण और प्रशासनिक सतर्कता का परिणाम है। श्री शाह ने इस सफलता का श्रेय कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की सतत मॉनिटरिंग और गंभीरता को देते हुए उन्हें व जिला शिक्षा अधिकारी को विशेष रूप से बधाई दी।

पेंचवैली 14 जुलाई से चलेगी नैनपुर तक

छिंदवाड़ा। पेंचव्हेली ट्रेन इन्दौर-सिवनी को 14 जुलाई से नैनपुर तक बढ़ाया जावेगा। इसी तरह छिंदवाड़ा-बैतूल पैसेंजर को सिवनी तक 14 जुलाई से बढ़ाया जा रहा है। रेल्वे ने इसके टाईम टेबिल जारी कर दिये हैं।

इन्दौर-नैनपुर पेंचव्हेली एक्सप्रेस इन्दौर ट्रेन न. 19343 से 1.05 बजे को छूटेगी और नैनपुर दूसरे दिन सुबह 6.30 बजे नैनपुर पहुंचेगी यह ट्रेन न. 19344 शाम को नैनपुर से 7 बजे छूटेगी और दूसरे दिन 12.45 बजे इन्दौर पहुचेगी।

सिवनी बैतूल पैसेन्जर

इसी तरह सिवनी -बैतूल पैसेंजर ट्रेन न.58830 सिवनी से सुबह 5.30 बजे छूटेगी और 12.35 बजे बैतूल पहुंचेगी। यही ट्रेन न.58830 बैतूल से 4 बजेू शाम को छूटेगी और 10.30 बजे सिवनी पहुचेंगी।

पेंचवैली को इन्दौर सुबह एवं बैतूल पैसेन्जर को इटारसी तक चलना चाहिये

रेलवे द्वारा ट्रेनों को बढ़ाना यात्रियों के हिसाब से ठीक है दोनो ट्रेनो ट्रेनों के लिए अलग अलग रैक लग रहे हैं। ये रैक नैनपुर एवं सिवनी में दिन एवं रात्री में खड़े रहेंगे। इन्दौर का व्यापारिक महत्व है रेल्वे अपने टाईमटेबिल में फेरबदल कर ट्रेन को सुबह इन्दौर पहुंचाये और शाम को इन्दौर से छूटे तो दूसरे दिन 10-11 बजे नैनपुर पहुंचे इससे इन्दौर जाने वाले यात्रियों का समय खराब नहीं होगा वह दिन भर व्यापारिक कार्य कर सकता है। इसी तरह सिवनी-बैतूल को इटारसी बढ़ाया जाना चाहिए। जिससे इटारसी से आगे जाने के लिए और भी ट्रेन मिलेगी।

सांसद की पदयात्रा...

छिन्दवाड़ा गांधीगंज के व्यापारी एवं पांढुर्णा शहर व जिले के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुये

छिन्दवाड़ा। दादाजी धुनीवाले के भजनों और गीतों की सुमधुर धुन में लीन होकर दादाजी धुनी वाले के भक्तगण दादाजी धुनीवाले खंडवा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे है। सांसद बंटी विवेक साहू अपने चौथे संकल्प को पूरा करने के लिए 14 दिवसीय 411 किलोमीटर की पदयात्रा पर अपने पदयात्रियों के साथ निरंतर पदयात्रा कर रहे है। पदयात्रा के नौवें दिन सांसद श्री साहू सहित दादा भक्त पदयात्रियों का हौसला बढ़ाने और पदयात्रा में शामिल होने के लिए छिन्दवाड़ा गांधीगंज से बड़ी संख्या में व्यापारीगण व छिन्दवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक सहित पांढुर्णा शहर और जिले के विभिन्न गांवों के प्रतिष्ठित नागरिकगण पदयात्रा में शामिल हुए। सांसद सहित पदयात्रा में चल रहे बड़ी संख्या में पदयात्री आशापुर मार्ग के घने जंगलों से होते हुए दादाजी धुनीवाले खंडवा के दरबार में माथा टेकने के लिए दादा भक्त निरंतर पदयात्रा कर रहे है। सांसद श्री साहू और दादा भक्त पदयात्रियों ने अपनी नौंवे दिन की पदयात्रा की शुरूआत चिखली से 4 जुलाई की सुबह रथ में स्थापित मां नर्मदा के जलकलश और दादाजी धुनीवाले की पूजा अर्चना और आरती के साथ की।

चिखली से सुबह प्रारंभ हुई पदयात्रा रात में चिल्हौर पहुंची

चिखली से प्रारंभ हुई पदयात्रा आशापुर के घने जंगलों और विभिन्न गांवों और कस्बों से होते हुए दोपहर में नांदा पहुंची। जहां पर सांसद श्री साहू और पदयात्रियों ने दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद प्रारंभ हुई यात्रा आशापुर के घने जंगलों और विभिन्न गांवों से होते हुए रात में चिल्हौर पहुंची। चिल्हौर में सांसद श्री साहू ने अपने पदयात्रियों के साथ पदयात्रा के साथ चल रहे रथ में स्थापित मां नर्मदा के जलकलश और दादाजी धुनीवाले की पूजा अर्चना और आरती एवं रात्रि भोजन के बाद विश्राम किया। 5 जुलाई की सुबह चिल्हौर से पदयात्रा प्रारंभ होगी जो दोपहर में बेहड़ा पहुंचेगी। बेहड़ा में दोपहर का भोजन करने के बाद पदयात्रा कालीघोड़ी आश्रम पहुंचेगें, कालीघोड़ी आश्रम में रात्रि विश्राम रहेगा। सांसद बंटी विवेक साहू की नौंवे दिन की पदयात्रा में छिन्दवाड़ा गांधीगंज के व्यापारी व शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और पांढुर्णा जिले के प्रतिष्ठित नागरिकगण शामिल हुए।

पुराने वरिष्ठ एवं अनुभवीअतिथि शिक्षकों को रखने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

छिंदवाड़ा। संपूर्ण मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्यप्रदेश भोपाल के आह्वान पर प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे अतिथि शिक्षकों की वर्तमान सत्र 2025- 26 में आ रही पोर्टल की परेशानी पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाईनिंग समस्या ,पोर्टल में पद प्रदर्शित नहीं होना पदो की संरचना में कमी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आज छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर को संघठन के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिले भर के अतिथि शिक्षको ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव एवं छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष कहार के निर्देशन में एवं जिला उपाध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा गया। जिला उपाध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि वर्तमान सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन नियुक्ति हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया चल रही है। जिसमें पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षकों की विभिन्न समस्याएँ आ रही है जैसे स्थानांतरण/उच्चपद प्रभार/अतिशेष/पद संरचना में अंतर/दर्ज संख्या में कमी इत्यादि कारणों से बाहर हुये विगत सत्र में कार्यरत, पुराने समस्त अनुभवी अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर वरीयता उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार दिया जाये। ततपश्चात रिक्त पदो पर नवीन अभ्यर्थियों की स्कूल में चयन प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाये।वही वर्तमान सत्र 2025 में लोकशिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 4.3 के अनुसार विगत सत्र किसी भी संस्था में एक ही विषय वर्ग के दो पदों में से वर्तमान में एक पद समाप्त होने पर अधिक स्कोर वाले अतिथि शिक्षको को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए है।

संयुक्त संघर्ष समिति का कन्हान क्षेत्र में कन्वेंशन सम्पन्न हुआ

परासिया। देश में नौ जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल से चक्का जाम और पहिया रुकेगा, जिसमें देश का मजदूर किसान नौजवान महिला सभी मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर लिया है। आज देश में एनडीए की सरकार में नये नये बदलाव देखने को मिल रही हैं,जिन मुद्दों को लेकर सत्ता से बाहर रही भाजपा और उसके सहयोगी दल निजिकरण, मंहगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, जीएसटी, आदि कई चीजों को लेकर सड़कों पर उतरते थे, आज उन्हीं सब बातों को लेकर पल्टी मारते हुए आम जनता विरोधी फैसले ले रही हैं। किसानों के खिलाफ, मजदूरों सहित आम जनता के खिलाफ और पूंजीपतियों और कार्पोरेट जगत के पक्षधर कानूनों को लागू करने पूरी ताकत झोंक रही हैं। जिसको लेकर देश के एक सरकारी संगठन को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय श्रम संगठनों ने नौ जुलाई को राष्ट्र व्यापी आम हड़ताल करने जा रही हैं।उसी तारतम्य में पेंच कन्हान पाथाखेड़ा क्षेत्र का संयुक्त कन्वेंशन डुंगरिया के दातला स्थित कन्हान व्हेली क्लब में तीन बजे से किया गया जिसकी अध्यक्षता पेंच कन्हान इंटक अध्यक्ष और परासिया के लोकप्रिय विधायक सोहन वाल्मीकि ने किया,एच एम एस वेकोलि कि ओर से जितेन्द्र मल,एटक से रामकेरा यादव, और सीटू वेकोलि से जगदीश डिगरसे ने कन्वेंशन की संबोधित किया।मंच पर कामेश्वर राय कि विशेष उपस्थिति रही साथ ही चारों संगठनों के तीनों क्षेत्रों के अध्यक्ष, महामंत्रियों ने अपनी बात रखी।मंच संचालन मनोज ठग ने किया।

मिलजुल कर मनाएंगे मोहर्रम....

एसडीएम ने शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी

अमरवाड़ा। अमरवाड़ा थाना में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक हुए एसडीएम हेमकरण धुर्वे एसडीओपी रविंद्र मिश्रा जिला भाजपा महामंत्री टीका राम चंद्रवंशी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र जैन विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा नगर निरीक्षक राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में शहर में एवं क्षेत्र में शांति और शालीनता के साथ मोहर्रम मनाया जावे नगर पालिका अधिकारी विद्युत विभाग पुलिस अधिकारी को उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए की परंपरा के अनुसार इस बार भी शांति सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारे के साथ सभी मिलकर कौमी एकता की मिसाल प्रस्तुत करेंगे पुलिस की ओर से फरियाद पुलिस बल लगाया जाएगा औरआवश्यकता अनुरूप महिला पुलिस बल भी तैनात रहेगा। नगर मेंताजिया के सफर मार्ग गंज बाजार से संत तारण तरण मार्ग से होते हुए गांधी चौक पर पटेली मोहल्ला बड़ा मोहल्ला आजाद वार्ड पर शहीद चौक फवारा में विशेष व्यवस्था नगर पालिका एवं बिजली विभाग ,सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग ,गंज बाजार से लेकर शहीद चौक बस स्टैंड से लेकर नगर पालिका तक यातायात व्यवस्था सुचारू बनाएंगे। मोहर्रम ताजिया दोपहर को गंज बाजार पहुंचेंगे फिर सहीद चौक फावारा मैं रखे जाएंगेरात्रि 8.30 बजे कर्बला की ओर प्रस्थान करेंगे।

राजा हत्याकांड में शिलांग पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी

शिलांग। करीब सवा माह पहले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या कर दी गई थी। हत्या में उसकी पत्नी सोनम सहित चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मामले में पुलिस जल्द ही चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, सोनम और तीनों आरोपियों ने जो दोपहिया वाहन किराए पर लिए थे, उनकी जीपीएस लोकेशन भी अहम सबूत है। क्योंकि, हत्या के समय दोनों वाहनों की लोकेशन एक ही थी। मामले में पुलिस ने कुछ दिन पहले इंदौर से प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स और गार्ड बल्लू उर्फ बलवीर, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

उनकी गवाही भी इस हत्याकांड में अहम होगी, क्योंकि उन्होंने सोनम और राज कुशवाह के कहने पर सबूत मिटाए थे। पुलिस ने राजा के शव के पास से जो टी शर्ट और हथियार जब्त किए हैं, वे भी आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत साबित होंगे। पुलिस ने उसकी फोरेंसिक जांच भी कराई है। उसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी है।

अब तक यह सबूत जुटाए: शिलांग पुलिस ने अब तक राजा हत्याकांड को लेकर रिवाल्वर, गहने, जलाए गए बैग के अवशेष, हत्या में प्रयुक्त हथियार, आरोपियों के कपड़े सहित अन्य सबूत जुटाए हैं। आरोपी विशाल ने हत्या के समय जो शर्ट पहनी थी, उसे भी पुलिस ने उसके घर से जब्त किया है। विशाल ने ही राजा के सिर पर पहला वार किया था। 23 मई को राजा रघुवंशी की सोनम सहित चार आरोपियों ने हत्या कर दी थी। शव को खाई में फेंक कर सोनम इंदौर आ गई थी। राज ने ही हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वह शिलांग नहीं गया था।

मोहर्रम की तैयारियां जोरों पर, ट्रैफिक किया डायवर्ट

भोपाल। मोहर्रम के जुलूस को लेकर पुराने शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज से 7 जुलाई को शहर के चार रास्तों पर शाम 6 बजे से रूट डायवर्ट किए जाएंगे। शाम से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्ग के उपयोग की बात कही है। भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड, भोपाल टॉकीज, शाहजहांनाबाद, रॉयल मार्केट, कोहेफिजा तिराहा, करबला के रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। इन रास्तों पर शाम 6 बजे के बाद यातायात का दबाव रहेगा।

इन रास्तों पर डायवर्ट होगा ट्रैफिक- भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड, भोपाल टाकीज, शाहजहांनाबाद, रॉयल मार्केट, कोहेफिजा तिराहा, करबला के रास्ते पर सभी प्रकार के मालवाहक, भारी और व्यवसायिक वाहनों पर रोक रहेगी।

एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग- राजाभोज एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहन भारत माता चौराहा, भदभदा चौराहा, साक्षी ढाबा तिराहा, नीलबड़ तिराहे से दाएं मुड़कर, नाथू बरखेड़ा रोड, मुगालिया छाप, खजूरी सड़क, खजूरी बायपास तिराहा-मुबारकपुर चौराहा होकर आवागमन कर सकेंगे। 6राजाभोज एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहन प्रभात चौराहा, जेके रोड, रत्नागिरि, अयोध्या बायपास मार्ग, भानपुर, करौंद चौराहा, नई जेल, गांधीनगर तिराहा होकर आ-जा सकेंगे। नए शहर से रेलवे स्टेशन की ओर जाने के लिए प्रभात चौराहा, परिहार चौराहा, 80 फीट रोड, बजरिया तिराहा होकर आवागमन कर सकेंगे।

आज प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज-यलो अलर्ट, 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी

भोपाल। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से प्रदेश के नदी नाले उफान पर है। कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को 28 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का ऑरेंज-यलो अलर्ट है। अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शनिवार को मंडला और डिंडौरी में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है।

जबलपुर में 3 इंच तक पानी गिरा- शुक्रवार को 27 से अधिक जिलों में बारिश हुई। जबलपुर में 72 मिमी यानी, करीब 3 इंच पानी गिर गया। नरसिंहपुर में 2.6 इंच, सागर में डेढ़ इंच, छतरपुर के नौगांव में सवा इंच, मंडला-दमोह में 1 इंच, दतिया-श्योपुर में पौन इंच, बालाघाट-रीवा में आधा इंच बारिश हुई। वहीं, भोपाल, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, छतरपुर के खजुराहो, टीकमगढ़, सिवनी, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, देवास, सीहोर, आगर-मालवा, विदिशा, मऊगंज, कटनी समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। रात के समय भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा।

चार दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि एक मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर से मप्र के दतिया, सीधी से होती हुई आसनसोल, कोलकाता होते हुए जा रही है। वहीं, एक भी प्रदेश से गुजर रही है। इसके अलावा प्रदेश में ही एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन सिस्टम एक्टिव है। इन तीनों सिस्टम की वजह से अति भारी या भारी बारिश का दौर चल रहा है। अगले चार दिन 8 जुलाई तक प्रदेश के आधे हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी हिस्से में सिस्टम का असर ज्यादा रहेगा।

सामाजिक समरसता कार्यक्रम

सायं 6:00 बजे | दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

अपराह्न 4:00 बजे | आई एस बी टी, ग्वालियर

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

गरिमामयी उपस्थिति

ज्योतिरादित्य सिंधिया
केन्द्रीय मंत्री, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

नरेन्द्र सिंह तोमर
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा

5 जुलाई, 2025

समरस समाज की स्थापना के सतत प्रयास

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की **जन्मभूमि महू , महानिर्वाण स्थल दिल्ली, दीक्षा भूमि नागपुर, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा स्थल लंदन 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' में सम्मिलित**

महू को अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित करते हुए **अम्बेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर एवं स्मारक संग्रहालय का विकास** एवं महू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ **अम्बेडकर नगर स्टेशन**

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना - स्व-रोज़गार के लिए डेयरी इकाई लगाने हेतु ₹42 लाख तक ऋण
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना - अनुसूचित जाति के युवाओं को ₹1 लाख तक की स्व-रोज़गार अनुदान सहायता
- डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना - एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता
- अम्बेडकर गौ-शाला विकास योजना - आधुनिक गौ-शालाओं हेतु 125-150 एकड़ शासकीय भूमि आवंटन
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना - अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को 10वीं-12वीं में सर्वोच्च अंक लाने पर ₹30 हजार का पुरस्कार
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना - अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हेतु अम्बेडकर फैलोशिप
- भोपाल में मध्यप्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम डॉ. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य - सागर में 258.64 वर्ग कि.मी. में प्रदेश का 25वां अभयारण्य

सीधा प्रसारण webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhypradesh @jansamparkMP JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
D-11058/25
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025